

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT

7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई ७ 2021 | अंक ०4



May 20

#WorldBeeDay

NATIONAL
BEE
DAY



ध्येयIAS®

most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय



विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.



क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय



कुरबान अली
मुख्य संपादक



आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारीयों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरुआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरुआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रुके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।



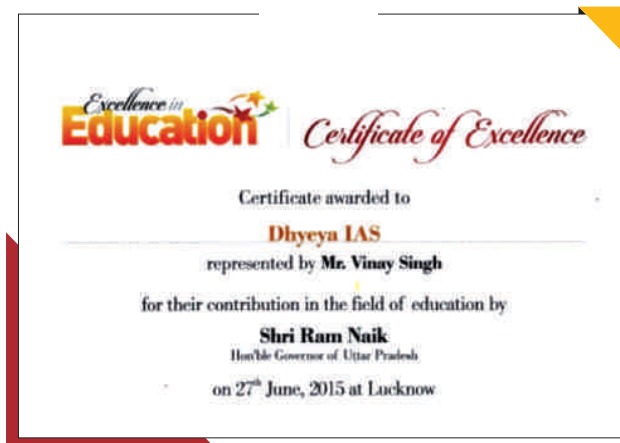
प्रस्तावना



ह मने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS



सं घ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका, फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➤ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➤ वयू. एच. खान
मुख्य संपादक	➤ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➤ आशुतोष सिंह
संपादक	➤ जीत सिंह ➤ अवनीश पाण्डेय ➤ ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	➤ अजय सिंह ➤ अहमद अली ➤ स्नेहा तिवारी
लेखक	➤ अशरफ अली ➤ गिराज सिंह ➤ हरिओम सिंह ➤ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➤ रंजीत सिंह ➤ रामराज अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➤ संजीव कुमार झा ➤ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➤ गुफ्रान खान ➤ राहुल कुमार
प्रारूपक	➤ कृष्ण कुमार ➤ कृष्णाकांत मंडल ➤ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➤ हरीराम ➤ राजू यादव

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2021 | अंक 04

7

विषय सूची

➤ सप्ताह के प्रमुख मुद्दे	1-14
➤ सप्ताह के चर्चित व्यक्ति	15-18
➤ सप्ताह के चर्चित स्थान	19-23
➤ सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस	24-27
➤ ब्रेन बूस्टर	28-35
➤ स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	36-40
➤ स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)	41-42

OUR OTHER INITIATIVES



Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper



DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/II, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009



सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- ◆ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थान शामिल
 - ◆ चक्रवात 'यास'
 - ◆ चंद्रग्रहण एवं सुपरमून
-

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- ◆ चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा
 - ◆ चीन का नया सामरिक राजमार्ग
 - ◆ भारत और ओमान के बीच दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण
 - ◆ भारत-इजराइल के बीच कृषि में सहयोग के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर
 - ◆ व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति बनाम भारत सरकार
 - ◆ वैक्सीन पर्यटन
-

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- ◆ हवाना सिंड्रोम
 - ◆ क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज
 - ◆ 'नेट जीरो बाय 2050' (Net Zero by 2050)
 - ◆ जीआई प्रमाणित 'शाही लीची'
 - ◆ व्हाइट फंगस
-

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- ◆ सूखा राशन दें, प्रवासी कामगारों के लिए सामुदायिक रसोई चलाएं: SC

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थान शामिल

चर्चा का कारण

- यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कराने के लिए देश से 9 स्थानों का नाम भेजा गया था, जिसमें से 6 स्थानों को स्वीकृति मिली है।

प्रमुख बिन्दु

- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत से वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल को जगह मिली है।
- 2019 की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है। इस गाइडलाइन के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में अब भारत के 48 स्थान शामिल हैं।

भारत में विश्व धरोहर स्थल

- वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। इन्हें दो भागों में बाँटा गया है, एक हैं सांस्कृतिक और दूसरे प्राकृतिक। 2017 में भारत के चार स्थानों में आयोजित होने वाले कुंभ मेला को भी यूनेस्को के सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। दुनिया भर

में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत छठवें स्थान पर आता है।

- साल 2019 में गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की चारदीवारी (परकोटा) को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था।

विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थान

- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व:** मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सरीसृप सहित हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियों और नीलगिरी क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का घर है। यहाँ बाघों की बड़ी आबादी भी है। इस जगह पर 1500 से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग के साथ 50 से अधिक रॉक शैल्टर हैं।
- वाराणसी के घाट:** विश्व की प्राचीनतम नगरी वाराणसी का गंगाघाट रिवर फ्रंट मुख्य रूप से सांस्कृतिक गुणों की दूसरी श्रेणी में आता है, अर्थात: इमारतों के समूह, अलग-अलग समूह या जुड़े हुए भवन, जो अपनी वास्तुकला या विज्ञान की दृष्टि से शानदार नमूने हैं।
- हायर बेनकल महापाषाण स्थल:** कर्नाटक में हायर बेनकल के 2,800 साल पुराने महापाषाण स्थल ने इस तथ्य के कारण अस्थायी सूची में जगह बनाई है कि यह सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापाषाण बस्तियों में से एक है जहाँ कुछ अंत्येष्टि स्मारक अभी भी बरकरार हैं।
- महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला:**

महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले हैं। इनमें शिवनेरी (शिवाजी का जन्मस्थान), रायगढ़, तोरणा (मराठा साम्राज्य का पहला किला), राजगढ़, साल्हेर-मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग (कासा), विजयदुर्ग और कोलाबा हैं।

- भेड़ाघाट-लम्हेटाघाट:** मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट, भारत के ग्रेंड कैन्यन के रूप में जाना जाता है। यह जबलपुर जिले का एक शहर है, जो जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यह नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की चट्टानों और उनके विभिन्न रूपात्मक रूपों के लिए जाना जाता है। नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ाघाट-लामेतघाट क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। 1828 में विलियम स्लीमैन द्वारा लैमेटा बेड से पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्र किया गया था।
- कांचीपुरम के मंदिर:** अध्यात्म, शांति और रेशम के लिए प्रसिद्ध कांचीपुरम प्राचीन मंदिरों से युक्त है जो वास्तुकला के चमत्कार को दर्शाता है। वेगावती नदी के तट पर स्थित इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1,000 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 126 (108 शैव और 18 वैष्णव) ही बचे हैं। इसकी समृद्ध विरासत पल्लव राजवंश की बंदोबस्ती रही है, जिन्होंने इस क्षेत्र को 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच अपनी राजधानी बनाया और द्रविड़ शैलियों में मंदिरों के निर्माण कराये।

2. चक्रवात 'यास'

चर्चा का कारण

- पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर से चक्रवाती तूफान, 'यास' ने उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए 26 मई के आसपास उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच तट को पार कर गया है।

प्रमुख बिन्दु

- इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। 'यास' तूफान का नामकरण इस बार ओमान देश ने किया है। 'यास' का मतलब होता है निराशा।
- यास के प्रभाव से सैकड़ों तटीय गांवों में

पानी भर गया है और लाखों घर उजड़ गए हैं। इससे बंगाल में ही एक करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से ओडिशा-बंगाल के कई जिले जलमग्न हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया और सैकड़ों तटबंध टूट गए हैं। राहत एवं बचाव दल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निम्न वायु-भार का तन्त्र है जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होते हैं। उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भाग में होती है, जहाँ का तापमान 20° से 25°C के आस पास रहता है। अधिकांश उष्ण चक्रवात डोलड्रम की पेटी के उत्तर अथवा दक्षिण में

विकसित होते हैं।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व की ऊष्मा एवं आर्द्रता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। इसमें निम्न भार वायु राशियाँ नहीं होती बल्कि सागर स्तर से कई सौ मीटर की ऊँचाई तक एक ही प्रकार का तापमान, आर्द्रता तथा वायु राशि होती है।

प्रभाव

- उष्ण चक्रवात प्रायः भारी तबाही मचाते हैं। इनसे जान-माल, फसलों तथा वृक्षों को भारी नुकसान होता है। तेज पवन के कारण सागर का जल ऊँची लहरों के द्वारा स्थल पर चढ़कर निचले तटों को जल मग्न कर देता है।

3. चंद्रग्रहण एवं सुपरमून

चर्चा का कारण

- 26 मई 2021 को आकाश में पूर्ण चंद्रग्रहण (Total lunar eclipse), ब्लड मून (blood moon) और सुपरमून (Supermoon) तीनों ही एक साथ दिखाई दिए।

प्रमुख बिन्दु

- विशेषज्ञों के मुताबिक चंद्रमा चंद्रग्रहण के बाद सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब 7 फीसदी बड़ा दिखाई दिया। सुपरमून पूरी दुनिया में दिखाई दिया लेकिन चंद्रग्रहण केवल दुनिया के कुछ ही हिस्सों में दिखाई दिया।
- चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान, एक ऐसी स्थिति आती है, जिसमें दोनों के मध्य दूरी सबसे कम (औसतन लगभग 360,000 किमी) होती है। इस स्थिति को 'उपभू' अथवा पेरिजी (Perigee) कहा जाता है। इसके विपरीत पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी (लगभग 405,000 किमी) पर होता है तो इसे 'अपभू' अथवा ऐपोजी (Apogee) कहा जाता है।

चंद्रग्रहण क्या है?

- चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है किन्तु प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता, यह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगता है। खगोलशास्त्रियों के अनुसार जब सूर्य के चारो तरफ पृथ्वी और पृथ्वी के चारो तरफ चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब इस स्थिति में चन्द्र ग्रहण लगता है।

सुपरमून

- सुपरमून पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का एक बड़ा आकार है। दरअसल चंद्रमा की पृथ्वी के चक्कर काटने की कक्षा अंडाकार है। इस वजह से कई बार यह पृथ्वी के काफी पास तक आ जाता है, जिससे हमें उसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देता है।
- सुपरमून का संबंध पूर्णिमा तिथि से है। यानि जिस दिन पूर्णिमा (Full Moon) तिथि हो और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदू पर हो तो इस स्थिति में ही सुपरमून लगेगा।

ब्लड मून

- दरअसल, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढक जाता है तो अंधेरा छा जाता है लेकिन पूरी तरह स्याह नहीं होता। इसके बजाए यह लाल रंग का दिखता है इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण को लाल या रक्त चंद्रमा भी कहा जाता है।
- सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश के सभी रंग होते हैं। पृथ्वी के वातावरण से गुजरने के दौरान प्रकाश में नीला प्रकाश छन जाता है जबकि लाल हिस्सा इससे गुजर जाता है। इसलिए आकाश नीला दिखता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा छा जाती है।
- चंद्र ग्रहण के मामले में लाल प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरता है और यह चंद्रमा की ओर मुड़ जाता है जबकि नीला प्रकाश इससे बाहर रह जाता है। इससे चंद्रमा पूरी तरह लाल नजर आता है। यह नारंगी या लाल से लेकर भूरे रंग का भी हो सकता है।

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा

चर्चा का कारण

- हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच (China's 17+1 cooperation forum with central and eastern European states) से इस्तीफा दे दिया है। लिथुआनिया ने इसे 'विभाजनकारी' (divisive) बताया है।

कारण

- हाल के महीनों में लिथुआनिया ने कई कदम उठाए जिससे बीजिंग नाराज हो गया, जिसमें चीनी निवेश को रोकना और ताइवान में एक व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा करना शामिल था। लिथुआनिया ने यूरोपीय संघ के साथी सदस्य देशों से, 'चीन के साथ, एक अधिक प्रभावी '27 + 1 दृष्टिकोण (27+1 approach) अपनाने का आग्रह किया है।
- पिछले वर्ष लिथुआनिया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा था कि वो कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक जवाब पर चर्चा करने के लिए आयोजित होने वाली बैठक में ताइवान को बुलाए। ताइवान की भागीदारी का चीन ने विरोध किया था जबकि अमेरिका ने समर्थन दिया था। इसके अतिरिक्त सीईई (CEE) के सांसद और नीति निर्माता हांगकांग में विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के खिलाफ जारी बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल थे।

17+चीन

- 17+1 पहल चीन की अगुवाई वाला एक समूह है जिसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में हुई थी और इसका मकसद चीन और मध्य

और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। साथ ही CEE क्षेत्र के विकास के लिए निवेश और व्यापार का इस्तेमाल होना था।

- इस व्यवस्था के तहत सदस्य देशों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं जैसे पुल, मोटरवे, रेलवे लाइन और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना था।

सदस्य देश

- इस पहल में EU के 12 सदस्य देश और पांच बाल्कन देश शामिल हैं- अल्बानिया, बोस्निया और हर्जोगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लात्विया, लिथुआनिया, मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया।
- इस मंच को मुख्य रूप से चीन की प्रमुख परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। 17+1 पहल को लेकर चीन की सोच रही है कि वो इसके जरिए यूरोप के उन देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करेगा जो पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले कम विकसित हैं।

संबंधों में गिरावट क्यों?

- निवेश संबंधी तकरार:** शुरुआत में चीन की तरफ से CEE देशों में निवेश के जो वादे किए गए वो उम्मीद दिलाने वाले थे लेकिन वक्त बीतने के साथ जो एलान चीन ने किए थे उनमें काफी कमी देखी गई। वास्तव में 17+1 पहल के तहत अलग-अलग शिखर सम्मेलनों में कई परियोजनाओं का प्रस्ताव

रखा गया था लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ कुछ परियोजनाएं पूरी हुई हैं। CEE देशों में चीन के साथ भविष्य की साझेदारी को लेकर निराशा का भाव है।

- बढ़ती दूरी:** जून 2020 में बेल्ट एंड रोड अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत हुए वर्चुअल सम्मेलन में सिर्फ सर्बिया, हंगरी और ग्रीस के प्रतिनिधि आए। 17+1 पहल में शामिल दूसरे सदस्य देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि चीन और CEE देशों के बीच रिश्ते किस कदर बिगड़ गए हैं।

- हुवावे समीकरण:** कुछ सीईई (CEE) देशों ने अमेरिका के साथ एक साझा घोषणापत्र पर दस्तखत किया जिसके तहत 5जी नेटवर्क के विकास में असुरक्षित कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें हुवावे भी शामिल है।

परिणाम

- लिथुआनिया के इस्तीफा देने के बाद इसे 16+1 मंच के रूप में जाना जाएगा।

बाल्टिक देश

- बाल्टिक राज्य (जिसे बाल्टिक्स, बाल्टिक देश या बाल्टिक प्रदेश भी कहा जाता है) उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहते हैं, जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं।

2. चीन का नया सामरिक राजमार्ग

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रणनीतिक रूप से अहम राजमार्ग (highway) का निर्माण पूरा कर लिया है। इससे चीन अरुणाचल प्रदेश के विवादित सीमा के साथ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच सकेगा।

प्रमुख बिन्दु

- चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण यारलुंग जांगबो ग्रैंड कैनियन के बीच (तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जैंगबो कहते हैं।) से होकर किया है जिसे दुनिया की सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है और जिसकी अधिकतम गहराई 6009 मीटर है।
- 67.22 किलोमीटर लंबा राजमार्ग चीनी शहर न्यिंग्ची में पैड टाउनशिप को मेडोग काउंटी के बैबंग टाउनशिप से जोड़ता है, जिससे दोनों के बीच यात्रा का समय आठ घंटे कम हो जाता है। राजमार्ग में 2.15 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। मेडोग तिब्बत का अंतिम प्रांत है, जो अरुणाचल प्रदेश (भारत) की सीमा के करीब स्थित है।
- इस राजमार्ग का निर्माण 2014 में शुरू हो गया था। यह राजमार्ग जिस मेडोग काउंटी को जोड़ता है वह तिब्बत की अंतिम काउंटी है और अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित है, जिसे लेकर चीन अवैध रूप से दावा करता है कि यह तिब्बत का ही हिस्सा है। हालांकि भारत ने हमेशा से अरुणाचल को अभिन्न मांगते हुए चीन के किसी भी दावे को दृढ़ता से खारिज किया है।



चीन द्वारा अन्य सामरिक निर्माण कार्य

- आधुनिक गांवों का निर्माण:** 2017 में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 'मध्यम रूप से अच्छी तरह से संपन्न गांवों' के निर्माण की योजना शुरू की, जिसके तहत भारत, भूटान, नेपाल और चीन की सीमाओं के साथ नगरी, शिगात्से, शन्नान और न्यिंग्ची प्रांतों तथा अन्य दूरदराज के इलाकों में 628 गाँव विकसित किये जाएंगे।
- पिछले वर्ष उपग्रह चित्रों में भूटान की सीमा के अंतर्गत 2-3 किमी में 'पंगडा' नामक एक नया गांव देखा गया। इसी तरह जनवरी 2021 में भी अरुणाचल प्रदेश के समीप 5 किलोमीटर दूर पर चीन द्वारा तीन गांवों के निर्माण किये जाने की खबरें सुर्खियों में थी। चीन के स्टेट काउंसिल इनफॉर्मेशन ऑफिस ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र पर नीति को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 2020 के अंत तक सुदूर प्रांत के

सीमा पर स्थिति कई गांवों को हाईवे से जोड़ दिया गया था और इन क्षेत्रों में स्थित सभी गांव में मोबाइल संपर्क की सुविधा हासिल हो चुकी है।

- रेलवे का निर्माण:** नवम्बर 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत में न्यिंग्ची से जोड़ेगा, यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। वर्ष 2006 में शुरू किये गए चिंगहई-तिब्बत रेलमार्ग (Qinghai-Tibet railway) के बाद यह तिब्बत के लिये दूसरा प्रमुख रेल लिंक है। रेलवे 'बाकी चीन से तिब्बत तक उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को परिवहन और स्थानीय उत्पादों को बाहर लाने में मदद करेगा'। यदि भारत चीन सीमा पर तनाव या युद्ध होता है, तो रेलवे रणनीतिक सामग्री की डिलीवरी के लिए 'फास्ट ट्रैक' के रूप में कार्य कर सकता है।

3. भारत और ओमान के बीच दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

प्रमुख बिन्दु

- इन दो समझौतों में एक समुद्री परिवहन समझौता भी शामिल है, जिस पर दिसंबर, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और एक अन्य समझौता, जिस पर वर्ष, 2018 में सहमति हुई थी, उसने भारतीय नौसेना को

ओमान के डुकम बंदरगाह पर सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की थी।

- भारत और ओमान ने वर्ष, 2018 में ओमान के डुकम बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

- डुकम बंदरगाह व्यापक पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह मुंबई से उड़ान भरने पर सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर क्षेत्र के पश्चिमी भाग में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच, भारत ने इस बंदरगाह की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में अपनी रुचि दिखाई थी।

भारत और ओमान के बीच संबंध

- ओमान, भारत का समुद्री पड़ोसी है। यह खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार भी है और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के लिये एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है।
- दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के अच्छे और मधुर संबंध हैं जिसका श्रेय ऐतिहासिक

सामुद्रिक व्यापारिक संपर्क, शाही परिवार का भारत के साथ अपनत्व और ओमान के निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय की अहम भूमिका को दिया जा सकता है।

- ओमान, भारत के इंडो-पैसिफिक विजन का एक हिस्सा है। भारत ओमान में कई परियोजनाओं की योजना बना रहा है। इसमें सेबासिक एसिड प्लांट शामिल है (जो मध्य-पूर्व में सबसे बड़ा है), यह परियोजना 1.2 बिलियन डॉलर की है। इसके अलावा, "लिटिल इंडिया" नामक एक एकीकृत पर्यटन परिसर का निर्माण 78 मिलियन अमरीकी डालर के तहत किया जाना जायेगा।
- भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्वि पक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह सेना अभ्यास अल नजाह एवं वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज आयोजित किया जाता है।

भारत के लिए ओमान का महत्व

- ओमान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि इसमें हिंद महासागर के सभी 1,700 किलो मीटर समुद्री तट के साथ औद्योगिक हब स्थापित हैं। ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पांचवाँ हिस्सा आयात करता है।
- ओमान में चार औद्योगिक मुक्त क्षेत्र हैं और चार समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। ओमान के औद्योगिक मुक्त क्षेत्र में 30 साल के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, मुनाफे के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई आयकर नहीं, मुद्रा विनिमय स्वतंत्रता की सुविधाएँ हैं।

4. भारत-इजराइल के बीच कृषि में सहयोग के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 तक के लिए तीन साल के एक संयुक्त कार्यक्रम (Indo-Israel Agriculture Action Plan - IIAP) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक ऐसे चार संयुक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं।

कृषि में सहयोग के क्षेत्र

- भारत और इजरायल 'भारत-इजरायल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र' और 'भारत-इजरायल उत्कृष्टता गांवों' को लागू कर रहे हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन-एमआईडीएच, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और एमएसएसएचएवी- अंतराष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी - इजराइल के सबसे बड़े जी2जी सहयोग का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के 12 राज्यों में 29 परिचालन केंद्र (Centres of Excellence) हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इजरायली कृषि-प्रौद्योगिकी के साथ प्रगतिशील-सघन खेती-बाड़ी को लागू करते हैं।



- नए कार्यक्रम के तहत कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र - 'विलेज ऑफ एक्सलेंस' (Villages of Excellence) - तैयार किया जायेगा। इसे 75 गांवों के भीतर 13 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ आठ राज्यों में बनाया जाएगा। यह किसानों की व्यक्तिगत आय को बढ़ावा देगा और उनकी आजीविका को बेहतर बनाएगा।
- भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में वर्ष 1993 से द्विपक्षीय संबंध रहा है। यह 5वीं भारत- इजराइल कृषि कार्ययोजना (आईआईएपी) है।

- यह नया कार्यक्रम कृषक समुदाय के लाभ के लिए कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्वि पक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। अब तक देश के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence - CoE) संचालन में हैं। हर साल, ये सीओई 2.5 करोड़ से अधिक गुणवत्ता वाली सब्जी पौध के बीज, 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फल पौधों का उत्पादन करते हैं तथा बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के बारे में 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित करते हैं।

तीन साल की कार्य योजना (2021-2023)

- तीन साल की कार्य योजना (2021-2023) दोनों देशों के बीच हमारी साझेदारी की शक्ति को प्रदर्शित करता है और उत्कृष्टता केंद्रों और उत्कृष्टता गांवों के माध्यम से स्थानीय किसानों को लाभान्वित करेगी।
- इस कार्य योजना का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों और सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा।

5. व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति बनाम भारत सरकार

चर्चा का कारण

- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बार फिर फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप (WhatsApp) की नई प्राइवसी पॉलिसी आठ फरवरी से लागू होने वाली थी लेकिन विवाद के बाद कंपनी ने प्राइवसी को मई तक टाल दिया था। अब फिर से नई गोपनीयता नीति को लेकर व्हाट्सएप लगातार अपने उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन दे रहा है, साथ ही व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति 15 मई 2021 से लागू हो गयी है।

व्हाट्सएप की नई गोपनीयता में क्या?

- व्हाट्सएप के मुताबिक जो लोग प्राइवसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वे व्हाट्सएप जुड़ी कई सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी की कंपनी उन्हें Limited Functionality Mode में डाल देगी। ये व्हाट्सएप यूजर्स अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यूजर्स वॉयस और वीडियो कॉल ना ही कर पाएंगे न उसका जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप आपके फोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे।
- फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी अब उन यूजर्स के अकाउंट की फैंसिलिटीज या फीचर्स को सिमित कर देगी जो प्राइवसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए व्हाट्सएप नई गोपनीयता नीति के बारे में उपयोगकर्ताओं को रिमाइंडर भेजना जारी रखेगा।
- वॉट्सएप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।



व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति विवादित क्यों है?

- व्हाट्सएप की नई पॉलिसी इससे जुड़े प्लेटफॉर्म और इसकी मूल कंपनी, फेसबुक और थर्ड पार्टी को यूजर का मेटाडेटा (यह वस्तुतः किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की विस्तृत (360-डिग्री) व्योरा उपलब्ध कराता है।) इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। नई पॉलिसी को सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य बताया गया है। हालांकि व्हाट्सएप ने नई गोपनीयता नीति में 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' (End-to-End Encryption) का प्रावधान अभी भी बरकरार है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि व्हाट्सएप उपभोक्ताओं के संदेशों को नहीं देख सकेगा और न ही उन्हें किसी के साथ साझा कर सकेगा।
- जानकारों का मानना है कि जब प्राइवसी पॉलिसी को मामला-दर-मामला आधार पर देखा जाता है, तो ऐसे डेटा का बहुत कम या कोई महत्व नहीं हो सकता है। लेकिन एक बड़े नजरिए से, मैक्रो डेटा ब्लॉक के पहलू की जांच की जाए तो देखेंगे की यूजर्स की गुप्त प्राथमिकताओं को लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह 'निजता पर साफ हमला' हो सकता है।
- फेसबुक के साथ उपयोगकर्ता का डेटा साझा करने के व्यावसायिक उद्देश्य से व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति का हालिया परिवर्तन यह स्थापित करता है कि अब व्हाट्सएप मात्र एक मध्यस्थ होने के बजाय उपभोक्ताओं के डेटा का मालिक भी है।

भारत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता

- भारत के डेटा सुरक्षा कानून की प्रक्रिया कई वर्षों से सुस्त पड़ी है, यदि वर्तमान में भारत में डेटा सुरक्षा कानून होता, तो व्हाट्सएप शुरुआत में ही इस अपडेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि यह पहली बार है जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसने कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का अनुसरण करेगा।
- मंत्रालय ने दोहराया है कि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव और उन्हें पेश करने का तरीका भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सूचनात्मक गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता की पसंद के मूल मूल्यों को कमजोर करता है।
- भारत के डेटा संरक्षण विधेयक पर पिछले कुछ समय से लंबी चर्चा हुई है, और इससे पहले कि न्यायपालिका कॉरपोरेट्स द्वारा गोपनीयता के आक्रमण के उदाहरणों के खिलाफ ठोस रुख अपना सके, इसमें सुधार जरूरी है।

भारत के पास विकल्प

- भारत जल्द ही जर्मनी के रास्ते पर जा सकता है, अगर वह प्रतिक्रियाओं को संतोषजनक नहीं पाता है, या एक ठोस डेटा संरक्षण विधेयक पारित होने तक अपडेट पर रोक लगाने के लिए मौजूदा अपडेट पर प्रतिबंध लगा सकता है।

6. वैक्सीन पर्यटन

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स ने पर्यटन के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोल दी हैं और हवाई यात्राओं की अनुमति भी दे दी है। कोविड -19 की दूसरी लहर और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के बीच “वैक्सीन टूरिज्म” शब्द गति पकड़ रहा है। दिल्ली-मास्को के लिए ‘अरेबियन नाइट्स टूर’ नामक दुबई बेस्ड ट्रेवल एजेंसी द्वारा वैक्सीन टूर पैकेज के ड्राफ्ट के बाद वैक्सीन टूरिज्म सुर्खियों में आया है।



क्या है वैक्सीन पर्यटन?

- वैक्सीन पर्यटन को “टीका प्राप्त करने के अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए विभिन्न देशों की यात्रा” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- ‘वैक्सीन टूरिज्म’ गत वर्ष से चलन में आया है। कोरोना की पहली लहर में, बीते साल कई टूर ऑपरेटरों ने कथित तौर पर विभिन्न देशों की यात्रा की पेशकश की थी। इस पैकेज में वैक्सीन की दो खुराक के बीच विभिन्न देशों में घूमने के अलावा अन्य लाभ देने का भी ऑफर दिया गया था। दुनियाभर में यह पर्यटन यात्रा का नया संस्करण बनकर उभरा है, जो पर्यटकों को वैक्सीन की डोज और लग्जरी हॉलिडे दोनों उपलब्ध कराता है।

वैक्सीन पर्यटन पैकेज के बारे में

- वैक्सीन पर्यटन पैकेज में एक होटल में 20 दिन का आवास, भोजन, उड़ानें और कुछ दिनों के दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपये है। मालदीव और अमेरिका जैसे देश भी इसी तरह के कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं ताकि विदेशों में लोगों को उनकी यात्रा के दौरान टीका

लगवाने की अनुमति मिल सके।

किन देशों में वैक्सीन टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है?

- भारत और थाईलैंड जैसे देश चिकित्सा या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए सबसे आम देशों में से एक हैं। कोरोना के बाद अब, यूरोप की कई टूर कंपनियां अमरीका, ब्रिटेन, रूस और मालदीव जैसे देशों में वैक्सीन टूरिज्म की पेशकश कर रही हैं। हाल ही, मध्य यूरोप के एक छोटे से गणराज्य सैन मैरिनो ने पिछले सप्ताह अपने यहां पहले वैक्सीन पर्यटकों के समूह का स्वागत किया। इसमें लातविया के चार लोगों का एक समूह शामिल था। समूह 26 घंटे में ही स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन हॉलिडे पैकेज का लाभ लेने वाला पहला पर्यटक दल बन गया। वैक्सीन पासपोर्ट और वैक्सीन टूरिज्म के साथ अमरीका और रूस भी अब अपने यहां इस चलन को बढ़ावा दे रहे हैं। रूस और मालदीव तो पिछले साल से ही ऐसे टूरिस्ट पैकेज की पेशकश करने पर काम कर रहे हैं, जो विदेशों में यात्रा करते समय टीकाकरण की सुविधा देते हैं। अमरीका में भी अब इसका चलन बढ़ रहा है।

- दक्षिण अफ्रीका के लोग कथित तौर पर वैक्सीन लगवाने के लिए जिम्बाब्वे की यात्रा कर रहे हैं। जबकि कनाडाई और दक्षिण अमरीकी नागरिक वैक्सीनेशन के लिए अमरीका की यात्रा कर रहे हैं।

वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में

- वैक्सीन पासपोर्ट दरअसल, एक तरह का दस्तावेज है जो साबित करता है कि किसी देश की यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने देश में कोविड-19 का टीका लगवा चुका है। इससे लोगों के लिए अब अन्य देशों की यात्रा करना आसान हो गया है। अन्य देशों में वैक्सीन पासपोर्ट के कुछ संस्करणों से यह भी पता चलता है कि हवाई सफर से पहले उस यात्री का कोरोना परीक्षण किया गया था और परिणाम निगेटिव है। कई एयरलाइंस, उद्योग समूह, गैर-लाभकारी और प्रौद्योगिकी कंपनियां ऐसे वैक्सीन पासपोर्ट्स पर काम कर रही हैं, जिन्हें लोग अपने स्मार्टफोन, ऐप या अपने डिजिटल वॉलेट में एक्सेस कर सकेंगे।

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. हवाना सिंड्रोम

चर्चा का कारण

- हाल ही में दुनिया भर में तैनात अमेरिकी अधिकारियों, डिप्लोमैट्स, जासूस और सैनिकों में एक नई रहस्यमयी मानसिक बीमारी देखने को मिल रही है। इसे 'हवाना सिंड्रोम' (Havana Syndrome) कहा जा रहा है।

प्रमुख बिन्दु

- अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (National Academies of Sciences) के मुताबिक यह बीमारी किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी की वजह से हो रही है। एनएसएस (NAS) ने निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण (Directed Microwave Radiation) को 'हवाना सिंड्रोम' का संभावित कारण माना है।

हवाना सिंड्रोम क्या है?

- वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी, नाक से खून और बेचौनी हो रही है। इस मामले के बाद इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा था।
- विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ छिपकर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने इसी तरह की घटनाओं की शिकायत चीन और रूस में भी की है। उन्होंने कहा कि दूतावास की इमारत के कुछ कमरों में उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा।
- इस बीमारी के कुछ लक्षणों में मतली,

थकान, मानसिक परेशानी और चक्कर आना शामिल हैं। इस बीमारी से संक्रमित होने पर, रोगी को पीड़ादायक सनसनाहट की आवाज महसूस होती है।

माइक्रोवेव हथियार

- ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार (direct energy weapons) हैं। इस हथियार के द्वारा किसी एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव ऊर्जा केंद्रित की जाती है। जो लोग उच्च तीव्रता वाले माइक्रोवेव पल्सेस के संपर्क में आते हैं, वे सिर में एक क्लिक या भनभनाने की आवाज की महसूस करते हैं। इस हथियार के तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। हालाँकि इसके कारण शारीरिक क्षति का कोई संकेत नहीं दिखता है।
- माइक्रोवेव हथियार की वेवलेंथ एक मिमी से लेकर एक मीटर जितनी होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज (100 सेंटीमीटर) और 300 गिगाहर्ट्ज (0.1 सेंटीमीटर) के बीच होती है। इन्हें हाई-एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है।
- युद्ध स्तर पर माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल कम ही देखा गया है। इसका उपयोग चेतावनी देने के लिए किया जाता है। यदि दुश्मनों पर माइक्रोवेव हथियार से हमला किया जाए तो उन्हें आंखों की समस्या, शरीर में हल्के घाव और अंदरूनी चोटें लग सकती हैं। फिलहाल भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन इस हथियार को

विकसित करने में जुटे हुए हैं।

- हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने पर माइक्रोवेव शरीर के टिश्यू का तापमान बढ़ा सकते हैं, जो सिर के भीतर शॉकवेव पैदा कर सकता है। जिसकी वजह से कई तरह की समस्या हो सकती है। हालाँकि, इस हथियार का इस्तेमाल करने पर मौत का खतरा नहीं होता है। फिलहाल माइक्रोवेव हथियार को लेकर कई देश शोध अध्ययन कर रहे हैं और हथियार को विकसित करने में जुटे हुए हैं।

अमेरिका के पास माइक्रोवेव हथियार

- अमेरिका के पास माइक्रोवेव हथियारों में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने बनाया है। इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को तितरबितर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक्टिव डिनाइल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जानकारों के अनुसार माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल कई तरह की मिसाइल को रोकने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

- वर्ष 1863 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक गैर-लाभकारी, सरकारी संगठन है। यह संगठन सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करता है।

2. क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज

चर्चा का कारण

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने क्यासानूर वन रोग (KFD) के तेजी से निदान के लिए अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए एक नया point-of-care test खोजा है, जो भारत में एक नई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या और चुनौती के रूप में उभर रहा है।

प्वाइंट-ऑफ-केयर टेस्ट

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology) द्वारा पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्ट विकसित किया गया है। यह KFD के निदान (diagnosis) के लिए फायदेमंद होगा, जिसे मंकी फीवर (monkey fever) भी कहा जाता है।

- यह बुखार आमतौर पर दूरदराज के क्षेत्रों में फैलता है जहां सैंपल हैंडलिंग और प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं की कमी होती है। इस प्रकार, पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्ट रोगी को जल्दी से प्रबंधित करेगा और वायरस के आगे प्रसार को नियंत्रित करेगा।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज क्या है?

- वर्ष 1957 में इस रोग की पहचान सबसे पहले कर्नाटक के क्यासानूर जंगल (Kysanur Forest) के एक बीमार बंदर में की गई थी, तब से प्रतिवर्ष 400-500 लोगों के इस रोग से ग्रस्त होने के मामले सामने आए हैं।
- यह रोग कीट-जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार (tick-borne viral haemorrhagic fever) है जो भारत के दक्षिण-पश्चिमी भाग के लिए स्थानिक है।

- यह फ्लैविविरिडे (Flaviviridae) परिवार के एक वायरस के कारण होता है। KFD वायरस के भंडार के रूप में कार्य करते हुए, संक्रमित हार्ड टिक (infected hard ticks) के काटने से मनुष्यों में वायरस फैलता है।

KFD वायरस (KFDV)

- यह एक विशिष्ट फ्लेविवायरस (flavivirus) है जिसका व्यास 40-60 nm है। KFDV के जीनोम में सिंगल-स्ट्रैंडेड और पॉजिटिव-सेंस RNA के 10,774 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो सिंगल पॉलीप्रोटीन को एनकोड करते हैं।
- KFDV का जीनोम अलखुरमा हेमोरेजिक फीवर वायरस (Alkhurma Hemorrhagic Fever Virus) के समान है, जो सऊदी अरब में पाया गया था।

Kysanur Forest Disease



Transmission

Transmission to humans may occur after a tick bite or contact with an infected animal

Signs and Symptoms

Chills, fever, headache, muscle pain with vomiting, gastrointestinal symptoms, bleeding

Risk of Exposure

People with recreational or occupational exposure to rural or outdoor settings

Monkeys, rodents, bats, shrews are susceptible to the virus

3. 'नेट जीरो बाय 2050' (Net Zero by 2050)

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency – IEA) द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न सरकारों को 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।
- इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन (NZE) हेतु 'नेट जीरो बाय 2050' नाम से अपना रोडमैप जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोडमैप है जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज कोप-26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है?

- 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' से तात्पर्य मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन स्थापित करना है।

आवश्यकता क्यों?

- यदि अभी भी देशों द्वारा जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं जिसमें वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' तक लाना तथा वैश्विक तापन को 1.5 °C तक सीमित करना शामिल है, को पूरी तरह से हासिल कर लिया जाए तो उसके बाद भी वे वैश्विक ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे होगी।

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए रोड मैप

- रिपोर्ट में लगभग 400 मील के पथर को शुद्ध-शून्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक नया रोड मैप सूचीबद्ध किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टिक परिवर्धन की स्थापना 2030 तक प्रति वर्ष 630 गीगावाट (GW) तक पहुंचनी चाहिए, पवन ऊर्जा को 390 गीगावाट तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

- लगभग 90% बिजली उत्पादन 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा से और शेष परमाणु ऊर्जा से आना चाहिए।

- कोई भी नया कोयला आधारित बिजली स्टेशन तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि वे अपने उत्सर्जन को पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल न करें।

- आंतरिक दहन इंजन वाली नई कारों की बिक्री 2035 तक समाप्त करनी होगी।

- वैश्विक बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 2030 तक 5% (वर्तमान में) से बढ़कर 60% हो जानी चाहिए।

- 2050 में तेल की मांग घटकर 24 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहनी चाहिए।

- वर्ष 2040 तक वैश्विक बिजली क्षेत्र को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचाना।

- रोडमैप में वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के वार्षिक परिवर्द्धन या वृद्धि को 630 गीगावाट तक पहुंचने और पवन ऊर्जा के 390 गीगावाट तक पहुंचने का आह्वान किया गया है।

- यह रेल और ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन के साथ क्षेत्रीय हवाई यात्रा की जगह उपभोक्ताओं द्वारा व्यवहार में बदलाव पर भी जोर देता है।

- IEA ने अपनी सिफारिश में नई जीवाश्म ईंधन आपूर्ति परियोजनाओं में निवेश को तुरंत समाप्त करने और 2035 तक गैसोलीन और डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री को रोकने के लिए कहा था।

इस रोडमैप का उद्देश्य

- घोषित 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' लक्ष्यों के प्रभावों की जांच करना तथा ऊर्जा क्षेत्र में उनके महत्व को बताना।
- वर्ष 2050 तक विश्व स्तर पर NZE प्राप्त

करने की दिशा में नया ऊर्जा-क्षेत्र मार्ग विकसित करना।

- निकट अवधि में कार्य करने हेतु सरकारों के लिये प्रमुख नीतिगत सिफारिशों को निर्धारित करना, अन्य सतत् विकास लक्ष्यों तक पहुंचने की दृष्टि से शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक दीर्घकालिक एजेंडा निर्धारित करना।

क्या किया जाना चाहिए?

- प्रौद्योगिकी तटस्थता को सामान्यतः सूचना या डेटा के रूप में शामिल ज्ञान पर निर्भरता के बिना, विकास, अधिग्रहण, उपयोग या व्यवसायीकरण हेतु अपनी आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त तथा उचित प्रौद्योगिकी चुनने के लिये व्यक्तियों और संगठनों की स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया जाता है।
- सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें सभी देश न्यायसंगत पारगमन दृष्टिकोण से तथा जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ नेतृत्व करती हैं, निवल शून्य में योगदान करते हो।
- जहां भी संभव हो क्षेत्र में एक व्यवस्थित पारगमन या ट्रांजिशन हो जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को कम करती हो।
- सुझाव:** वर्ष 2050 तक वैश्विक लक्ष्य को शून्य उत्सर्जन तक ले जाने हेतु 400 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—
- वर्ष 2050 तक वैश्विक बिजली उत्पादन को बढ़ाने हेतु रोडमैप में निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं:
 - 714% अधिक नवीकरणीय ऊर्जा।
 - 104% अधिक परमाणु ऊर्जा।
 - 93% कम कोयला (कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) के साथ सभी शेष कोयला।
 - 85% कम प्राकृतिक गैस (CCS के साथ 73%)।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आलोचना

- IEA ने 'जलवायु न्याय' के सिद्धांत की

- अनदेखी करते हुए महत्वपूर्ण उत्सर्जकों पर विचार नहीं किया।
- विकसित देशों को GHG उत्सर्जन की कीमत पर औद्योगिक क्रांति से लाभ हुआ, जिसने जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विकसित देशों के पास डीकार्बोनाइज करने हेतु अर्थव्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जिससे गरीब और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर चुनाव करने के लिये वित्तपोषण और नवाचार को व्यवस्थित करने का विकल्प मिल जाता है।
- संभावित रूप से ऊर्जा की कम खपत हेतु व्यवहार परिवर्तन पर अधिक निर्भर होने की आवश्यकता है।
- अर्थव्यवस्थाओं में रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने हेतु उन्हें विनियमित करना आवश्यक होगा।

4. जीआई प्रमाणित 'शाही लीची'

चर्चा का कारण

- हाल ही में बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची (GI certified Shahi Litchi) की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है।

प्रमुख बिन्दु

- जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है।
- शाही लीची के निर्यात के लिए पादप-स्वच्छता प्रमाणन पटना में नव स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सिरा इंटरप्राइजेज इसका निर्यात कर रहा है।
- शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता की है।

शाही लीची (Shahi Litchi)

- जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद वर्ष 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची (Shahi Litchi) बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था।
- शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण, मुजफ्फरपुर स्थित 'लीची प्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार' को दिया गया है।
- बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है।

- उल्लेखनीय है कि चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- लीची का पारदर्शी, स्वादिष्ट बीजचोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद रूप में पसंद किया जाता है।
- भारत का बिहार राज्य लीची के उत्पादन मामले में काफी आगे है।

भौगोलिक संकेतक क्या है?

- भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिह्न या संकेत (जीआई) का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा चिह्न, जो वस्तुओं की पहचान (यथा-कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ या विनिर्मित वस्तुएँ आदि) एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यतः योगदान देती हैं।
- इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है।
- यह दो प्रकार के होते हैं- पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं जैसे शैम्पेन, दार्जिलिंग आदि। दूसरे प्रकार में गैर-भौगोलिक

पारम्परिक नाम हैं जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबद्ध है जैसे अल्फांसो, बासमती, रोसोगुल्ला आदि।

• जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

किन वस्तुओं, पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है-
- 1. **कृषि उत्पादों:** जैसे चावल, जीरा हल्दी, नींबू आदि।
- 2. **खाद्यान्न वस्तुओं:** जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद आदि।
- 3. **वाइन और स्पिरिट पेय:** जैसे शैम्पेन और गोआ के एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि।
- 4. **हस्तशिल्प वस्तुएं (हैंडीक्राफ्ट्स):** जैसे मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क तथा इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां (टेराकोटा) और औद्योगिक उत्पाद आदि।

जीआई टैग से लाभ

- जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है।
- जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है।

- जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है।
- इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक टैग के कानून

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।

- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है।

5. व्हाइट फंगस

चर्चा का कारण

- कोरोना महामारी के दौर में ब्लैक फंगस के साथ ही व्हाइट फंगस का खतरा भी बढ़ने लगा है। हाल ही में, बिहार के पटना में 'व्हाइट फंगस' (White fungus) अर्थात 'कैंडिडियासीस' (Candidiasis) के कम से कम चार मामलों का पता चला है।

क्या है व्हाइट फंगस?

- विशेषज्ञों का कहना है कि व्हाइट फंगस ज्यादा खतरनाक है। यह हमारे आसपास व त्वचा पर ही मौजूद रहता है। जैसे ही पनपने का अवसर मिलता है, वह तेजी से शरीर के अंदर पहुंचकर अंगों को प्रभावित करने लगता है। खास बात यह है कि इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं। व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस से अलग तरीके की बीमारी है। इसका असली नाम, कैंडिडियासिस है। यह ज्यादातर आईसीयू में दाखिल मरीजों में पाया जाता है। कहीं दिनों से एंटी बायोटिक दवाइयां ले रहे हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक के साथ यह फंगल इन्फेक्शन भी फैल जाता है। यह आईसीयू में अक्सर पाया जाता है।

व्हाइट फंगस के लक्षण

- यह संक्रमण, व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अथवा पानी जैसे द्रव्यों अथवा पदार्थों में यह फफूंद होता है उसके संपर्क में आने से व्यक्तियों में फैल सकता है 'व्हाइट फंगस' के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन इनका टेस्ट नेगेटिव आता है; इस संक्रमण की पहचान सीटी-स्कैन या एक्स-रे के माध्यम से की जा सकती है।

प्रभाव

- 'व्हाइट फंगस' मनुष्य के फेफड़ों के साथ नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, गुप्तांग और मुंह को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज के अंग फेल होने से मौत भी हो सकती है। जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, उन्हें ये संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आते हैं।

व्हाइट फंगस सावधानियां

- विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बचने के लिए नाक, मुंह को स्वच्छ रखें। मास्क के प्रयोग में बेहद सावधानी बरतें। इसके अलावा दांत और जीभ की सफाई भी कुछ घंटों के अंतराल पर करते रहें। इसके बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं-
 - कई रिपोर्टों से पता चला है कि व्हाइट फंगस का इलाज एंटी फंगल दवा से संभव है।
 - ताजा फल खाएं।
 - घरों में रोशनी आने दें।
 - गंदी सतह को छूने के बाद हाथ-पैर जरूर धोएं।
 - फ्रिज में अधिक समय तक रखे या डिब्बा बंद चीजों का सेवन ज्यादा करने से बचें।

क्या है ब्लैक फंगस?

- दिल्ली के एम्स अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के अनुसार, ब्लैक फंगस कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। यह पहले भी हम बहुत बार देख चुके हैं। जिस भी मरीज जिनकी इम्युनिटी बहुत कमजोर है, खासतौर पर जिनकी डायबटीज बहुत ज्यादा है, कैंसर के मरीज हैं या फिर इम्यूट सिस्टम कमजोर हैं

उनमें यह फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है।

- यह फंगस इन्फेक्शन ऑपरचुनिस्टिक है, यानी सामान्य तौर पर यह हमारे आस पास ही रहती है। यह हवा में, मिट्टी में या फिर किसी भी नमी वाली जगह में पायी जाती है लेकिन हमारे पास इम्युनिटी का एक कवच होता है, जिससे यह हमारे ऊपर असर नहीं डालती है। लेकिन जब इम्युनिटी कम होती है तो यह हमला करता है।

- इसके लक्षणों में सिर दर्द होता है,
- आंखों के पास या आंखों के पीछे की तरफ दर्द या फिर नाक बंद हो जाती है,
- नाक से खून आने लगना, काले रंग का पानी आना,
- चेहरे पर सूजन आना, पलकें गिरना

क्या है येलो फंगस?

- इस फंगस का नाम म्यूकर सैप्टिकस है। यह अभी तक इंसानों में नहीं पाया जाता था। अगर हम नाक साफ करते हैं और घाव जो जाता है तो यह उसे भरने नहीं देता है। इस घाव से खून और पस रिसता रहता है। इसे ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी खतरनाक माना जा सकता है।

लक्षण क्या हैं?

- आलस आना,
- तेजी से वजन गिरना,
- भूख ना लगना,
- आंख में पस जम जाना,
- इसके साथ ही येलो फंगस शरीर के घाव को भरने नहीं देता है।

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि

1. सूखा राशन दें, प्रवासी कामगारों के लिए सामुदायिक रसोई चलाएं: SC

चर्चा का कारण

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण देश में सभी राज्यों को फंसे हुए प्रवासी कामगारों को बिना किसी राशन-कार्ड के शुष्क राशन वितरित करने और उनके लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया है। यह निर्देश, देश भर में प्रवासियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के आलोक में शीर्ष अदालत द्वारा शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दौरान जारी किये गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- अदालत ने इसके लिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी 'आत्मनिर्भर भारत योजना' अथवा किसी अन्य वैकल्पिक योजना का उपयोग करने संबंधी निर्णय राज्यों के विवेक पर छोड़ा है।
- 'आत्मनिर्भर भारत योजना' वर्ष 2020 के मई और जून में प्रवासी श्रमिकों को शुष्क राशन देने के लिए शुरू की गई थी।
- शीर्ष अदालत की पीठ ने निर्देश दिया दिया है, कि प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा सामुदायिक रसोई की जगहों के बारे में "व्यापक प्रचार" किया जाए, ताकि सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
- सूखा राशन प्रदान करते समय राज्यों के अधिकारियों को उन प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र पर जोर नहीं देना है जो उस समय उनके पास नहीं होगा और फंसे हुए

प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई स्वयं-घोषणा पर उन्हें सूखा राशन दिया जाए।

- इसके अलावा, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा राज्यों को भी फंसे हुए प्रवासी कामगारों, साथ ही उनके परिवारों के लिए एनसीआर में अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उन्हें दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराया जाए।

न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गए निर्देश

- दिल्ली एनसीटी, यूपी और हरियाणा राज्य (एनसीआर में शामिल जिलों के लिए) यह सुनिश्चित करेंगे कि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में) को पर्याप्त परिवहन प्रदान किया जाए जो अपने घर लौटना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय में जिला प्रशासन ऐसे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पहचान कर सकता है और सड़क परिवहन या ट्रेन द्वारा उनके परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकता है। प्रवासी मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त उपाय करने के लिए भारत संघ रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
- दिल्ली एनसीटी, यूपी राज्य और हरियाणा राज्य (एनसीआर में शामिल जिलों के लिए) फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों (राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र में) में सामुदायिक रसोई खोलेंगे ताकि वे और उनके परिवार के सदस्य जो फंसे हुए हैं उन्हें एक दिन में दो भोजन मिल सकें।

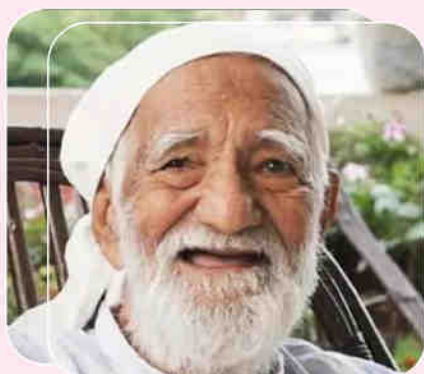
आवश्यकता क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने अदालत को सूचित करते हुए कहा था कि प्रवासी कामगारों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं।
- किंतु फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है।
- अब असली मुद्दा यह है, कि इस तरह के उपायों में केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले व्यक्तियों, अर्थात राशन-कार्ड धारकों को शामिल किया जा सकता है। जबकि, बड़े शहरों में काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास राशन कार्ड मिलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।



सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

सुन्दरलाल बहुगुणा



डेविड एटनबरो



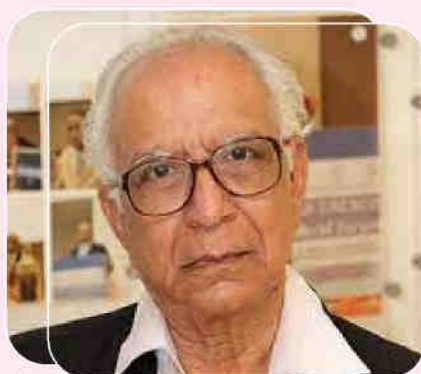
शाजी एन.एम



श्रीकुमार बनर्जी



प्रो. एम एस नरसिम्हन



युआन लोंगपिंग



डॉ नरेंद्र ध्रुव बत्रा



1. सुन्दरलाल बहुगुणा

- हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आन्दोलन के नेता सुन्दरलाल बहुगुणा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया, वे 94 वर्ष के थे।

सुन्दरलाल बहुगुणा के बारे में

- सुन्दरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी, 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उनको विशेष रूप से चिपको आन्दोलन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया। चिपको आन्दोलन के अलावा टिहरी बाँध के विरुद्ध आन्दोलन किया।

पुरस्कार

- सुन्दरलाल बहुगुणा को 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, परन्तु उन्होंने पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया था। वर्ष 1986 में उन्हें Right Livelihood Award से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड और 2009 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिपको आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा बहुगुणा के सहयोगी चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

चिपको आन्दोलन के बारे में

- चिपको आन्दोलन भारत में वनों के संरक्षण



के लिए शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1973 उत्तराखंड में हुई थी। इस आन्दोलन का उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना था। इस आन्दोलन में सुन्दरलाल बहुगुणा, सुरक्षा देवी, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. डेविड एटनबरो

- विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो (Sir David Attenborough) को इस वर्ष नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसीडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी सर डेविड एटनबरो को वैश्विक नेताओं, प्रमुख निर्णय निर्माताओं और आम जनता को जलवायु कार्रवाई के महत्व के प्रति जागरूक करने, मौजूदा प्रगति

पर वार्ता करने और COP26 के दौरान लिये जाने वाले निर्णयों और कार्रवाइयों को उजागर करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा 'COP26 पीपुल्स एडवोकेट' के रूप में 95 वर्षीय डेविड एटनबरो आगामी छह माह में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें जून में कॉर्नवल (इंग्लैंड) में आयोजित होने वाला G7 शिखर सम्मेलन भी शामिल है, ताकि जलवायु और प्रकृति की रक्षा संबंधी मुद्दे



को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिक स्थान दिया जा सके।

3. शाजी एन.एम

- हाल ही में केरल के 'ट्यूबर मैन (Tuber Man)' नाम से प्रसिद्ध शाजी एन.एम. (Shaji N.M.), को 'पालतू प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of domesticated species)' की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।

शाजी एन.एम के बारे में

- शाजी एन.एम., लगभग 200 कंद फसलों (tuber crops) की एक विस्तृत श्रृंखला को संरक्षित करते हैं, जिनमें बड़ी अरबी (Yam), छोटी अरबी, जिमीकंद, अरारोट, शकरकंद,

मीठे आलू, कसावा और चाइनीज- आलू शामिल हैं। इनके लिए PPV-FR प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्थापित 'प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड' 2015 सहित कई राज्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अतिरिक्त सात बार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

भारत जैव विविधता पुरस्कार

- भारत जैव विविधता पुरस्कार 2012 में, भारत सरकार द्वारा UNDP इंडिया के साथ साझेदारी में, जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और प्रशासन के उत्कृष्ट मॉडलों



की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में 2 लाख नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

4. श्रीकुमार बनर्जी

- परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीकुमार बनर्जी का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

श्रीकुमार बनर्जी के बारे में

- श्रीकुमार बनर्जी का काम भौतिक धातु विज्ञान पर आधारित था। बनर्जी को प्रेशराइज्ड हैवीवाटर रियेक्टरों में इस्तेमाल होने वाले तथा दाब ट्यूब में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिकेशन शेड्यूल के विकास का आधार तैयार करने का श्रेय भी जाता है। बनर्जी ससेक्स यूनिवर्सिटी समेत दुनिया के अनेक शिक्षण संस्थानों में अतिथि प्रोफेसर भी रहे। वह एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु प्रतिष्ठान का नेतृत्व किया जब भारत और अमेरिका ने अपने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और परमाणु क्षति विधेयक के लिए नागरिक दायित्व कानून (Civil Liability for Nuclear Damage Bill) बनाया।
- वे IIT, खड़गपुर से धातु विज्ञान में B. Tech पूरा करने के बाद 1968 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के धातुकर्म विभाग



में शामिल हुए थे। 1974 में, उन्हें BARC में उनके काम के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। वह 2004 से 2010 तक BARC (Bhabha Atomic Research Centre) के निदेशक थे। उन्हें परमाणु प्रक्रियाओं में विशेष मिश्र धातुओं के उपयोग का व्यापक ज्ञान था।

योगदान

- श्रीकुमार ने भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना का नेतृत्व किया था, जब राजनीतिक और विशेषज्ञ विवादों में थी कि भारत अपनी परमाणु स्वायत्तता खो देगा यदि उसने

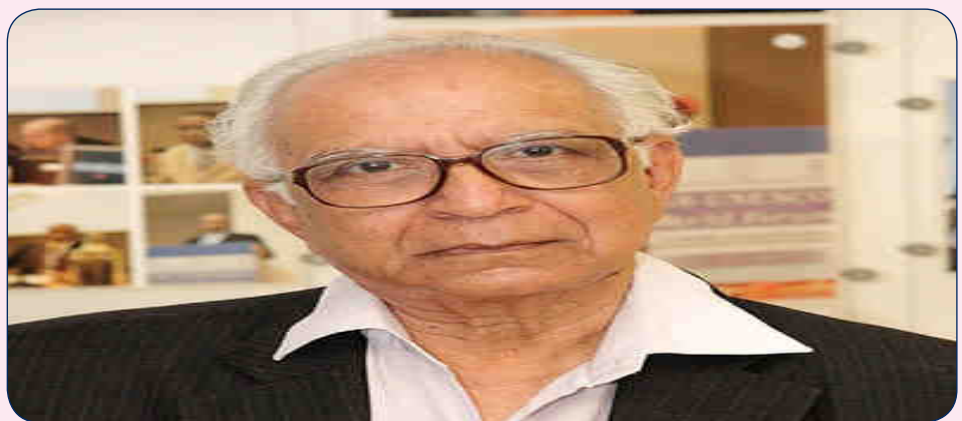
अमेरिका के साथ 123 संधि (123 Pact) या अमेरिका-इंडिया असैनिक परमाणु समझौते (US - India Civil Nuclear Agreement) पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उन्हें विश्वास था कि इससे भारत को फायदा होगा।

पुरस्कार

- उन्हें 1989 में “विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार” से सम्मानित किया गया था और 2005 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

5. प्रो. एम एस नरसिम्हन

- प्रतिष्ठित गणितज्ञ प्रो. एम एस नरसिम्हन का 16 मई, 2021 को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। सीएस शेषाद्रि के साथ वे ‘नरसिम्हन-शेषाद्रि प्रमेय’ के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ‘अवकल ज्यामिति’ (Differential geometry) और ‘बीजगणितीय ज्यामिति’ (Algebraic geometry) में अग्रणी योगदान दिया था। वे 2006 में विज्ञान के लिए ‘किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार’ से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय थे। वे 1982 से 1986 तक अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) की कार्यकारी समिति के सदस्य और IMU के विकास और विनियम आयोग (1986-94) के अध्यक्ष थे।
- प्रोफेसर नरसिम्हन ‘द रॉयल सोसाइटी, लंदन’, ‘इंडियन एकेडेमी ऑफ साइंसेज’



और ‘द एकेडेमी ऑफ साइंसेज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड’ (TWAS) के फेलो थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (1988) के ‘श्रीनिवास रामानुजन पदक’ के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण (1990) और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ‘शेवेलियर डी

लशऑर्ड्रे डू मेरिट’ (Chevalier de l'ordre du Merite) से सम्मानित किया गया था। गणित के लिए TWAS पुरस्कार (1987), भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार (1994) तथा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1975)।

6. युआन लोंगपिंग

- हाल ही में चीन के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक 'युआन लोंगपिंग' का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संकरित चावल (Hybrid Rice) संबंधी इनकी खोजों की वजह से चीन को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई और दुनिया भर में कृषि का स्वरूप बदल गया। इन्हें चीन में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए "हाइब्रिड चावल के पिता" के रूप में माना जाता है।
- युआन का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था। उन्होंने वर्ष 1973 में उच्च उत्पादन वाले धान की संकर प्रजाति विकसित की थी, जिसकी बाद में बड़े पैमाने पर चीन में खेती की गई और स्थायी रूप से चावल का उत्पादन बढ़ा। उल्लेखनीय है कि 1970 के

दशक में, उन्होंने 'नन-यू नंबर 2 (Nan&you No-2) नामक पहला हाइब्रिड चावल युग्म विकसित किया था। इस प्रक्रिया के तहत दो भिन्न मूल-जनकों के संयुग्मन से उत्पन्न होने वाली संतति, अपने मूल जनकों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, अधिक उपज देती है तथा बाहरी बाधाओं का बेहतर प्रतिरोध करती है। पूरे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पैदा होने वाले हाइब्रिड चावल के रूप में, दुनिया भर के किसानों ने उनकी तकनीकों से लाभ उठाया है।

- वर्ष 2004 में, उन्हें "उच्च उपज वाली संकर चावल किस्मों के प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक सामग्री और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में उनकी सफलता की



उपलब्धि" के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2001 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया।

7. डॉ नरेंद्र ध्रुव बत्रा

- हाल ही में भारत के डॉ नरेंद्र ध्रुव बत्रा फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष चुने गए हैं। बत्रा ने अध्यक्ष पद के लिए एफआईएच की 47वीं कांग्रेस में हुए चुनावों में अपने बेल्जियम के प्रतिद्वंद्वी मार्क काउड्रोन को बेहद नजदीकी मुकाबले में 63-61 से पराजित किया। बत्रा पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले 2016 में डॉ बत्रा एफआईएच के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और एशियन

हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष थे। डॉ बत्रा वर्ष 2024 तक एफआईएच के अध्यक्ष बने रहेंगे।

- अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक विश्व निकाय के 92 साल पुराने इतिहास में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सदस्य भी हैं। उल्लेखनीय है कि बत्रा को हॉकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2014 में प्रतिष्ठित एफआईएच प्रेजिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था।



सप्ताह के चर्चित स्थान

माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी



गलवान घाटी



ताइवान जलडमरूमध्य



सतकोसिया गॉज



टीगरे क्षेत्र



कूनो पालपुर नेशनल पाक



पुणे में भारत का पहला कृषि-निर्यात सुविधा केंद्र



1. माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी (Mount Nyiragongo Volcano)

- हाल ही में कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य में स्थित माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी (Mount Nyiragongo volcano) में विस्फोट हुआ है।

माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी (Mount Nyiragongo volcano)

- यह विश्व का सबसे खतरनाक तथा सक्रीय ज्वालामुखी है। यह 'विरुंगा पर्वत' का एक भाग है, इसकी ऊँचाई 3,470 मीटर है।
- यह ज्वालामुखी रिफ्ट (Albertine Rift) से जुड़ा है।
- यह ज्वालामुखी कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य में विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इस ज्वालामुखी का मुख्य क्रेटर 2 किमी. चौड़ा है। इसी में लावा झील भी शामिल है। नारागोंगो और न्यामुरागिरा (Nyamuragira) अफ्रीका में 40 प्रतिशत ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जिम्मेदार है।

विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान (Virunga National Park)

- यह कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में अल्बर्टिन रिफ्ट घाटी में स्थित है। इस वर्ष 1925 में खोला गया था। इसे वर्ष 1994 से विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया था।

ज्वालामुखी के बारे में

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह (भूपटल) पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख

आदि बाहर आते हैं।

- पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं वही जब यह मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है एवं इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर निकलते हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर धन-जन की व्यापक हानि होती है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए। उदाहरण के लिए इटली के दो प्रसिद्ध शहर पम्पियाई और हरक्युलैनियम ज्वालामुखी विस्फोट से बर्बाद हो गए।
- हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होते हैं। इससे ना केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे की क्रेटर झील, लैकोलिथ, फैंकोलिथ इत्यादि बल्कि कई खनिजों समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा होते हैं।

ज्वालामुखी के प्रकार

- ज्वालामुखी तीन प्रकार होते हैं-
 1. सक्रिय ज्वालामुखी
 2. सुषुप्त ज्वालामुखी
 3. मृत ज्वालामुखी
- सक्रिय ज्वालामुखी:** उन ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जिन पर समय- समय पर



विस्फोट होता रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसली का एटना और स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी एवं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है।

- सुषुप्त ज्वालामुखी:** उन ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े होते हैं लेकिन उनमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखीयों में इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजीयामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ एवं अंडमान और निकोबार का नारकोडम ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है।
- मृत ज्वालामुखी:** ऐसे ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जो कई युगों से शांत हैं एवं उनमें विस्फोट होना बंद हो गया है। संसार की कुछ मृत ज्वालामुखीयों में म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोनाको, ईरान का कोह सुल्तान इत्यादि शामिल है।

2. गलवान घाटी

- हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के जमावड़े ने भारत-चीन के मध्य तनाव को और बढ़ा दिया है। चीनी सेना के जमावड़े के प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सतर्क कर दिया।



पृष्ठभूमि

- भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए गतिरोध का कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के समानांतर, गलवान घाटी में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सड़क का निर्माण माना जा रहा है। इसे सीमा सड़क संगठन (BRO) ने बनाया है। बीआरओ भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ-साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है।
- इसके अलावा दिसंबर 2022 तक भारत द्वारा भी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में

फैली सीमा के साथ सभी 61 महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3,417 किलोमीटर तक होगी।

- गलवान घाटी, गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नदी का स्रोत नियंत्रण चीन की ओर स्थित अक्साई चीन में है, यह नदी पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है जो नियंत्रण रेखा के पार भारत की ओर श्योक नदी में मिलती है।
- गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन (चीन नियंत्रित) के बीच रणनीतिक रूप में स्थित है। इसके पश्चिमी छोर पर श्योक नदी और 'दरबुक-श्योक'

दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क मार्ग स्थित है।

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल

- LAC एक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो भारत और चीन को अलग करती है।
- भारत और चीन के बीच यह विवादित सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में भी जाना जाता है, को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख, कश्मीर), मध्य क्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम, अरुणाचल)।

3. ताइवान जलडमरूमध्य

- अमेरिका के "स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत" की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के तौर पर एक अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से होकर गुजरने की घटना को लेकर चीन ने इसे भड़काऊ कदम बताते हुए इस क्षेत्र की शांति व स्थिरता की अनदेखी करने वाला करार दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी सैन्य विमान और युद्धपोत समय-समय पर ताइवान जलडमरूमध्य और विवादित दक्षिण चीन सागर के उस इलाके में नौवहन की स्वतंत्रता को दर्शाने के लिये संचालन करते रहते हैं जिसपर चीन अपने क्षेत्र के तौर पर दावा करता है। फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई और ताइवान दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के दावों का विरोध करते हैं।
- सामरिक विशेषज्ञ के अनुसार अमेरिकी कार्रवाई ताइवान के स्वतंत्र बलों को गलत संकेत भेज रही है, जानबूझकर क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर रही है और पूरे ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रही है।



ताइवान जलडमरूमध्य के बारे में

- ताइवान जलडमरूमध्य 180 किलोमीटर चौड़ी है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। इसे फॉर्मोसा जलडमरूमध्य के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है। संपूर्ण जलडमरूमध्य एशिया के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है।

ताइवान के बारे में

- ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। यह देश अपने आसपास के कई द्वीपों से मिलकर बना है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। यह देश का वित्तीय केन्द्र भी है और यह नगर देश के उत्तरी भाग में स्थित है। ताइवान ऐतिहासिक तथा संस्कृतिक दृष्टि से चीन का अंग रहा है, पर इसकी स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता को लेकर चीन के साथ विवाद है।

4. सतकोसिया गॉर्ज

- हाल ही में ओडिशा के सतकोसिया गॉर्ज में महानदी नदी के ताजे पानी में लुप्तप्राय घड़ियाल प्रजाति का प्राकृतिक अवस्था में ब्रीडिंग देखी गई है। यह एक घोंसले में कम से कम 28 बच्चों को घड़ियाल आबादी के कायाकल्प में जुटे अधिकारियों द्वारा देखा गया है। गौरतलब है कि 1972 में घड़ियाल का जनसंख्या प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। महानदी नदी में 'मुगर' और 'घड़ियाल' नामक मगरमच्छ की दो प्रजातियाँ हैं। हाल के वर्षों में घड़ियाल आबादी की निगरानी पर विशेष बल दिया गया। 2007 में सतकोसिया को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया और 2014 में कोर क्षेत्र की सुरक्षा में वृद्धि किया गया और सतकोसिया गार्ज को मछली पकड़ने से मुक्त क्षेत्र बना दिया गया।
- सतकोसिया गॉर्ज का नाम अंगुल से 60 किमी.

दक्षिण में स्थित टिकरपाड़ा के निकट महानदी के संकरे विस्तार 'सतकोष' या सात मील है, के आधार पर किया गया है। इसे वर्ष 1976 में अभयारण्य घोषित किया गया था। यह ओडिशा के चार जिलों अंगुल, बुद्ध, कटक तथा नयागढ़ में विस्तारित है। भू-आकृति विज्ञान के दृष्टिकोण से सतकोषिया गार्ज महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ महानदी पूर्वी घाट के ठीक दाई ओर से निकलती है जो शानदार घाट का निर्माण करती है।

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य

- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश शामिल हैं। इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यतः चंबल नदी के रूप में ये अभयारण्य



5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके कोर क्षेत्र में लगभग 400 किमी लंबी चंबल नदी आती है। इसी नदी पर एक दूसरा अभयारण्य भी है जो कोटा के पास है। इसका नाम जवाहर सागर अभयारण्य है। यह मुख्यतः घड़ियालों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें अन्य कई प्रकार के जीव-जंतु और जलचर भी पाए जाते हैं।

5. टीगरे क्षेत्र

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इथियोपिया के टीगरे क्षेत्र में विस्थापित आबादी के साथ लिंग आधारित हिंसा पर गहरी चिन्ता जताई है। यहां पिछले कई महीनों की लड़ाई के कारण, हिंसा प्रभावित व विस्थापन के शिकार लोग, गम्भीर खाद्य असुरक्षा का भी सामना कर रहे हैं।

टीगरे क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- यूएन एजेंसी के अनुसार टीगरे और अमहारा व अफार के सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं और किशोर लड़कियों की हालत बेहद खराब है। हजारों महिलाओं के पास स्वास्थ्य व संरक्षण सेवाओं तक पहुँच नहीं है। शिरे नगर में प्रभावित इलाकों में लगभग 12 हजार घरेलू विस्थापित रहते हैं। इन क्षेत्रों में अगर मानवीय राहत स्थिति को बेहतर बनाने के लिये कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणामस्वरूप अगले कुछ महीनों में गम्भीर कुपोषण की स्थिति पैदा हो सकती है। विदित

ही कि टीगरे में लड़ाई पिछले वर्ष 4 नवम्बर को सुरक्षा बलों और टीगरे जन स्वतन्त्रता मोर्चा (टीपीएलएफ) के बीच शुरू हुई थी।

इथियोपिया के बारे में

- इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है। इसे इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का दसवाँ सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या और दक्षिण सूडान इथियोपिया के सीमावर्ती देश हैं। यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल-रुद्ध देश है।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका (अफ्रीका का सींग) पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर



में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। इसको मध्ययुगीन काल में बिलाद अल बरबर कहा जाता था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश-इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया हैं।

6. कूनो पालपुर नेशनल पार्क

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव ट्रस्ट (इडब्ल्यूटी) की ओर से 8 चीतों को देने का फैसला किया है। इनमें पांच नर चीता और तीन मादा दिए जा रहे हैं। नवंबर अंत तक 14 चीते लाए जाएंगे, जिसे कूनो पालपुर नेशनल पार्क (MP) में बसाया जायेगा।

घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब 70 साल बाद भी फिर भारत में चीते बसाने की तैयारी है। यही नहीं कूनो में चीते आने के बाद हमारा मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, घडियाल स्टेट और गिद्ध स्टेट के बाद चीता स्टेट भी बन जाएगा।

कूनो पालपुर नेशनल पार्क के बारे में

भारत में चीतों की स्थिति

- 1951 में अंतिम बार देश में चीता की उपस्थिति दर्ज की गई थी जिसे शिवपुरी के जंगलों में 1951 में देखा गया था। बाद में वर्ष 1952 में इस जानवर को देश में विलुप्त

- यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में इस वन्यजीव अभ्यारण के लिए 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में



इस क्षेत्र में वृद्धि की गयी। इस वन्यजीव अभ्यारण में भारतीय भेड़िया, बन्दर, भारतीय तेंदुआ तथा नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं।

7. पुणे में भारत का पहला कृषि-निर्यात सुविधा केंद्र

- हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के सहयोग से महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MCCIA) ने पुणे में भारत का पहला कृषि-निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है।

संबंधित पहलुओं पर कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा इसके अलावा यह व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए निर्यात गृहों के दौरे का आयोजन करेगा, खरीदार-विक्रेता बैठकें आयोजित करेगा।



कृषि-निर्यात सुविधा केंद्र के बारे में

- यह सुविधा केंद्र वैश्विक मानकों के अनुसार कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा और कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन-स्टॉप-सेंटर के रूप में काम करेगा। यह केंद्र संभावित निर्यातकों के विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर अपने विशेषज्ञों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। यह

नाबार्ड

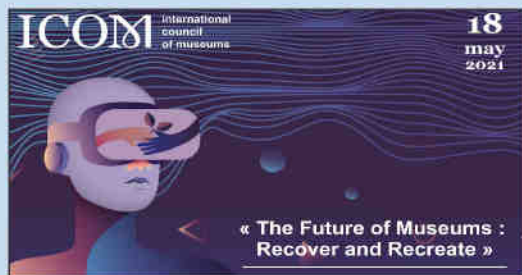
- यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी। 2010 में नाबार्ड की प्रदत्त

राशि 2,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। यह ग्रामीण ऋण संरचना की एक शीर्ष संस्था है जो कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।



सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस



विश्व मेट्रोलॉजी दिवस



विश्व मधुमक्खी दिवस



अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस



विश्व कछुआ दिवस



अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस



अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस



1. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस

- प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों की समझ और जागरूकता विकसित करने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) मनाया जाता है।
- वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम “हम समाधान का हिस्सा हैं” (We're Part Of The Solution) है।

जैव विविधता क्या है?

- जैव विविधता से आशय जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है जो विभिन्न प्रजातियों के मध्य, प्रजातियों के भीतर एवं पारितंत्र की विविधता को शामिल करते हैं। सर्वप्रथम वाल्टर जी. रासन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रायः जैव विविधता को तीन भागों में बांटा जाता है—
 - अनुवांशिक जैव-विविधता:** यह एक ही प्रजाति में पायी जाने वाली एक ही जाति के मध्य विभिन्नता को दर्शाती है, उदाहरण के लिए एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी।
 - प्रजातीय जैव-विविधता:** प्रजातियों के मध्य पायी जाने वाली विविधता को प्रजातीय जैव-विविधता कहा जाता है। जैसे चारों ओर वृक्षों, पौधों, झाड़ियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना।
 - पारिस्थितिकी जैव-विविधता:** विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों

की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी जैव-विविधता कहलाती है, उदाहरण राजस्थान में ऊँट की अधिकता आदि।

जैव विविधता का महत्व

- जैव विविधता से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए भोजन, औषधि, लकड़ी, ईंधन, चारा इत्यादि।
- जैव विविधता कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें प्रतिरक्षी भी बनाती है।
- जैव विविधता के विभिन्न घटक पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही वह संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण आदि।
- जैव विविधता से कार्बन डाइऑक्साइड समेत हरित गैसों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- जैव विविधता पृथ्वी पर एक संतुलन बनाए रखती है, उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा पारिस्थितिकी विविधता के साथ-साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है।
- आपदा के समय जैव विविधता एक अवरोधक का काम करती है; उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन आदि।
- जैव विविधता सांस्कृतिक और नैसर्गिक लाभ भी प्रदान करती है।



जैव विविधता का संरक्षण

- जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रायः दो विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं:
 - स्वस्थाने संरक्षण (In-situ conservation):** संरक्षण की इस विधा में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियाँ व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। संरक्षण की इस विधि के तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व आदि की स्थापना की जाती है।
 - बहिस्थाने संरक्षण (Ex-situ conservation):** संरक्षण की इस विधा में किसी संकटग्रस्त पादप या जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन, चिड़ियाघर, एक्वेरियम इत्यादि को रखा जाता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

- समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत ‘द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम’ (ICOM) ने 1977 में की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ताकि देश विदेश की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा सके।

भारत में संग्रहालय दिवस

- भारत में इस दिन कई संग्रहालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत देश में 40 से अधिक संग्रहालय हैं। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमारी धरोहर है, जिसे संग्रहालय संजोए रखता है। अगर संग्रहालय न होती तो आज हमारी सभ्यता और संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर होती। इन संग्रहालयों से हमें न केवल अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं



कि संग्रहालय प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशियों, मूर्तिकला, अन्य चीज, इतिहास आदि का भंडार गृह है।

3. विश्व मेट्रोलाजी दिवस

- हर साल 20 मई को विश्व मेट्रोलाजी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलाजी से संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलाजी दिवस 2021 का विषय : स्वास्थ्य के लिए मापन (Measurement for Health) है। इस विषय के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्रों में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

विश्व मेट्रोलाजी दिवस का इतिहास

- यह दिवस 20 मई 1875 से पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतराष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो (BIPM) बनाया गया था। इस कन्वेंशन ने माप के साथ-साथ, विज्ञान, वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की थी। अंतराष्ट्रीय भार



और माप ब्यूरो (BIPM) एक अंतराष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 20 मई, 1875 को हुई थी, इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट-क्लाउड में है। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 61 है।

4. विश्व मधुमक्खी दिवस

- विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ प्रायोजित दिवस है। जनसा ने 18वीं शताब्दी में मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक ईजाद की थी। जनसा का जन्म 20 मई, 1734 को स्लोवेनिया में हुआ था। उन्हीं के जन्मदिवस पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है।

खतरा मंडरा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लगभग 33% दुनिया के खाद्य उत्पादन का मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, इस प्रकार वे पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता के संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक हैं।



1860 के तहत किया गया है। यह कृषकों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बीज उपलब्ध करवाता है। NBB को वित्त की प्राप्ति राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिये होती है।

मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य

- मधुमक्खियां हमारे पारितंत्र के अभिन्न अंग हैं। हमारे स्थानीय पारितंत्र के स्वास्थ्य के अच्छे संकेतक भी हैं। आज कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त किए जा रहे कई कीटनाशकों से इनके अस्तित्व पर

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board-NBB)

- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका गठन सोसायटी अधिनियम

5. विश्व कछुआ दिवस

- अमेरिकी टोर्टोइस रेस्क्यू (एटीआर) द्वारा विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2021 विश्व कछुआ दिवस का विषय 'टर्टलस रॉक!' (Turtles Rock!) है।

अमेरिकी कछुआ बचाव (एटीआर) के बारे में

- कछुओं की प्रजातियों को बचाने और उसकी रक्षा के लिए गैरलाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टोयज

रेस्क्यू (एटीआर) की स्थापना 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना विश्व भर में मौजूद कछुओं और उनके खत्म हो रहे निवास की रक्षा करने के लिए लोगों की मदद करने के उद्देश्य से की गई थी।

कछुओं के बारे में

- कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों (लगभग 200 मिलियन वर्ष) में से एक मानी जाती है और ये प्राचीन प्रजातियां स्तनधारियों, चिड़ियों, सांपों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे।



जीववैज्ञानिकों के मुताबिक, कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सके क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है।

6. अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाता है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अपनाया गया था।

इतिहास

- 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों जैसे- भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मलावी, युगांडा और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक चाय व्यापार के प्रभाव के बारे में नागरिकों, सरकारों का ध्यान आकर्षित करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, गरीबी और भूख से लड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सिर्फ चाय से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसका एक मकसद चाय उत्पादकों और चाय मजदूरों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कोशिश भी करना है। भले ही चाय उत्पादक देश काफी लाभ कमाते हैं लेकिन चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब होती है। एक तो उनको उचित वेतन नहीं दिया जाता है और साथ ही काम करने की स्थिति भी काफी खराब होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चाय मजदूरों की काम की स्थिति, मजदूरों के अधिकार, दिहाड़ी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा को भी प्रोत्साहित करना है। यह दिन



इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से चाय उत्पादक देशों में चाय मजदूरों के योगदानों पर प्रकाश डाला जाता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसी दिन (29 मई) को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी। यह एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे। 2008 में महान पर्वतारोही हिलेरी के निधन के बाद नेपाल ने हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने साल 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। इस दिन काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि जुंको तबई (जापान) एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली (1975) विश्व की

पहली महिला है और बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ये 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी।

माउंट एवरेस्ट बारे में

- यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। यह हिमालय पर्वत का भाग, जो नेपाल में अवस्थित है। इसका नाम भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इससे पहले इस चोटी को चोटी-15 के नाम से जाना जाता था। 1954 ई. में इसकी ऊँचाई का मापन किया गया तब इसकी ऊँचाई 8848 मीटर ज्ञात की गयी थी। परन्तु नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 05 मई 1999 को जीपीएस उपग्रह के प्रयोग द्वारा इसकी ऊँचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की।



माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी के तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नेपाल में इसे सगरमाथा और तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से भी जाना जाता है।



ब्रेन बूस्टर

01

बागवानी उत्पादों हेतु दूसरा वर्चुअल व्यापार मेला

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एपीडा (APEDA) द्वारा बागवानी उत्पादों पर केंद्रित दूसरा वर्चुअल व्यापार मेला (Virtual Trade Fair-VTF) शुरू किया गया है।



2. मुख्य बिन्दु

- यह वर्चुअल व्यापार मेला (वीटीएफ) तीन दिवसीय है। इसे 27 से 29 मई, 2021 के दौरान आयोजित किया जा रहा है।
- इस वर्चुअल व्यापार मेले में विश्व के प्रमुख आयातकों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए गए अनूठे फल, सब्जियां और फूलों को प्रदर्शित किया गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 471 से अधिक प्रदर्शनी में भाग लेने वाले उत्पादकों या निर्यातकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। वहीं लगभग 543 आगंतुक/आयातकों ने वीटीएफ में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है।
- ताजी सब्जियों, ताजे आम, अनार और अंगूर और अन्य ताजे फलों के उत्पादक या निर्यातकों ने अपने उत्पादों को विश्व भर के मौजूद आयातकों के लिए प्रदर्शित किया है।
- वीटीएफ में भारत, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, सूरीनाम, अफगानिस्तान, जापान, आइसलैंड, मालदीव और ब्रुनेई के आयातक भाग ले रहे हैं।

5. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है।
- इसे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पॉल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको आदि उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके अतिरिक्त, एपीडा को सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक और गैर-मादक पेय, अनाज और अनाज उत्पाद, मूंगफली और अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी, ग्वार गम, फूल और फूल उत्पाद, हर्बल और औषधीय पौधे जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3. वर्चुअल व्यापार मेला (Virtual Trade Fair-VTF)

- कोविड-19 महामारी की वजह से यात्रा और व्यापार सीमित होने के कारण, एपीडा ने भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बनाए रखने और नए बाजारों की खोज के लिए वीटीएफ की अवधारणा शुरू की है।
- दुनिया भर के खरीददारों ने वीटीएफ के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
- वीटीएफ में निर्यातकों और आयातकों की बैठकें ऑडियो और वीडियो सत्रों के माध्यम से बिना किसी बाधा के आयोजित की जाती हैं। इसमें सुविधा कार्यशालाएं, उत्पाद लॉन्च, लाइव स्ट्रीम और वेबिनार भी आयोजित किए जाते हैं।
- निर्यातकों और आयातकों के बीच ऑनलाइन बातचीत होती है और इस तरह की बातचीत के दौरान डेटा का आदान-प्रदान पूरी तरह से सुरक्षित होता है।
- इस तरह के वर्चुअल आयोजन न केवल लागत प्रभावी होते हैं बल्कि उत्पादकों को ऐसा मंच प्रदान करते हैं; जहां खरीदार और विक्रेता रियलटाइम में प्रदर्शनियों या मेलों का अनुभव लेते हुए आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं।

4. पहला वर्चुअल व्यापार मेला

- एपीडा ने 10-12 मार्च, 2021 के दौरान पहला वीटीएफ आयोजित किया था, जिसमें 404 से अधिक विदेशी कारोबारियों/आयातकों ने भाग लिया था।
- इस मेगा वर्चुअल इवेंट के लिए 313 घरेलू उत्पादकों/ निर्यातकों को पंजीकृत किया गया था, जहां 128 स्टालों को विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया था। जिसमें बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली और मोटे अनाज आदि शामिल थे।

02

मालदीव में भारत का नया वाणिज्य दूतावास

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है।



2. प्रमुख बिन्दु

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है।
- भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं।
- भविष्य के लिए भारत की दूरगामी सोच में 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) नीतियाँ हैं। इन नीतियों में मालदीव का प्रमुख स्थान है।
- अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति और बढ़ेगी और इससे वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।
- भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी से भारतीय कंपनियों को वहाँ के बाजारों में अपनी पैठ बनाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इससे "आत्मनिर्भर भारत" के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर भी सीधा असर होगा।

3. नेबरहुड फर्स्ट नीति

- भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) के तहत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है।
- इस नीति के तहत सीमा क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी एवं सांस्कृतिक विकास तथा लोगों के आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- हाल ही में भारत द्वारा पड़ोसियों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने से 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' को और बल मिला है।
- गौरतलब है कि भारत ने अपनी कोविड -19 वैक्सीन कूटनीति के तहत भूयान और मालदीव को वैक्सीन की पहली खेप भेजी थी।

4. भारत-मालदीव संबंध

- भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है।
- मालदीव और भारत के बीच राजनैतिक संबंध के अलावा सामाजिक, धार्मिक और कारोबारी रिश्ता भी रहा है। मालदीव में लगभग 25 हजार भारतीय भी निवास करते हैं। भारतीय समुदाय मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है।
- मालदीव के विकास में भारत एक प्रमुख भागीदार रहा है और उसने मालदीव के कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना करने में सहायता की है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) फरवरी 1974 से मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- भारत ने मालदीव को उसकी आवश्यकता के समय हमेशा सहायता की पेशकश की है। मालदीव में 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुँचाने वाला भारत पहला देश था।

5. मालदीव

- मालदीव, हिन्द महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
- दरअसल यहाँ प्रवाल द्वीप पाये जाते हैं। इसलिए यह देश पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है।
- मालदीव, जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है।
- मालदीव की राजधानी माले है।

03

09 देशों में 'वन स्टॉप सेंटर'

1. चर्चा में क्यों?

- महिला और बाल विकास मंत्रालय (WCD), भारत सरकार ने 26 मई, 2021 को यह घोषणा की है कि, सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए WCD विदेश मंत्रालय (MEA) के सहयोग से 09 देशों में 10 वन-स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा।
- जिन 09 देशों में 'वन-स्टॉप सेंटर' हैं, वे हैं:- ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई. सऊदी अरब को छोड़कर हर देश में एक केंद्र होगा। सऊदी अरब में दो केंद्र स्थापित किए जाएंगे।



2. वन स्टॉप सेंटर (OSC) क्या हैं?

- वन-स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है।
- OSC योजना निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित है। केंद्र सरकार OSC के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- दिसंबर, 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद उषा मेहरा आयोग ने फरवरी, 2013 में 'वन स्टॉप सेंटर' की सिफारिश की थी।
- वर्तमान में, भारत में 700 वन स्टॉप सेंटर हैं। भारत की योजना वर्ष, 2021 तक पूरे देश में 300 और OSC स्थापित करने की है।

3. जिन सेवाओं के लिए ये योजना बनी है

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं
- चिकित्सा सहायता
- प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता
- मनो-सामाजिक सहयोग एवं परामर्श
- कानूनी सहायता और परामर्श
- आश्रय
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

4. वन-स्टॉप सेंटर: उद्देश्य

- निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का शिकार बनने वाली महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं की तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनोवैज्ञानिक या परामर्श सहायता, कानूनी सहायता, रहने के लिए आश्रय सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ-साथ मुफ्त पुलिस और अदालती कार्यवाही के दौरान सहायता करना है।

5. सुरक्षा की आवश्यकता क्यों

- लिंग आधारित हिंसा (GBV):** यह एक वैश्विक स्वास्थ्य, मानवाधिकार और विकास संबंधी मुद्दा है, और यह, भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नस्ल और धर्म को पार करते हुए दुनिया के हर कोने में हर समुदाय और देश को प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' की आवश्यकता है।
- 'हिंसा उन्मूलन' पर वर्ष 1993 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद 1, में लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार- लिंग आधारित दुर्व्यवहार में, लैंगिक हिंसा से संबंधित किसी भी कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है, या होने की संभावना है, तथा सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने, ऐसे कृत्यों की धमकी देने, जबरदस्ती करने या मनमाने ढंग से उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने, को शामिल किया गया है।

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme -UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for the Conservation of Nature-IUCN) द्वारा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 (Protected Planet Report, 2020) जारी की गयी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2010 में हुए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देशों द्वारा सहमत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है।



5. भारत में संरक्षित क्षेत्र

- संरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। रक्षित क्षेत्र भिन्न प्रकारों के होते हैं और उन्हें अलग-अलग स्तरों का संरक्षण दिया जाता है। कुछ समुद्री क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं।
- भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत कवर करता है।
- भारत ने अपने संरक्षित क्षेत्रों को चार कानूनी श्रेणियों में व्यवस्थित रूप से नामित किया है – राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व।

2. रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- संरक्षित क्षेत्र में वृद्धि:** वर्ष 2010 से 82 प्रतिशत देशों और क्षेत्रों ने संरक्षित क्षेत्र और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (other effective area-based conservation measures - OECM) के अपने हिस्से में वृद्धि की है।
- 2010 के बाद से लगभग 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि पिछले दशक में संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में 42 प्रतिशत क्षेत्र और जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप मई 2021 तक कम से कम 22.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर (16.64 प्रतिशत) भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र और 28.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (7.74 प्रतिशत) तटीय जल और महासागर संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के भीतर आ गए हैं।
- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र:** औसतन 62.6 प्रतिशत प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र (key biodiversity areas -KBA) या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के साथ ओवरलैप करते हैं। प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र ऐसी साइटें हैं जो स्थलीय, मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता की वैश्विक दृढ़ता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों और ओईसीएम के भीतर प्रत्येक केबीए का औसत प्रतिशत स्थलीय के लिए 43.2 प्रतिशत, अंतर्देशीय जल के लिए 42.2 प्रतिशत और समुद्री (राष्ट्रीय जल के भीतर) के लिए 44.2 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2010 के बाद से प्रत्येक मामले में 5 प्रतिशत अंक या उससे कम की वृद्धि हुई है, जो समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी वृद्धि है।

3. प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट संरक्षित क्षेत्रों के अलावा ओईसीएम का डेटा शामिल करने वाली श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। यह यूएनईपी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर (UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के समर्थन से जारी की जाती है। गौरतलब है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है।
- इस रिपोर्ट का वर्ष 2020 का संस्करण आइची जैव विविधता लक्ष्य 11 की स्थिति पर अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है। आइची जैव विविधता लक्ष्य 11 का उद्देश्य वर्ष 2020 तक 17% भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसके 10% तटीय जल एवं महासागरों का संरक्षण करना है।

4. सुझाव

- इस रिपोर्ट में मौजूदा आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों को पहचानने और मान्यता देने का भी आह्वान किया गया है, साथ ही आशा व्यक्त की गयी है कि स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों और निजी संस्थाओं के प्रयासों से के मौजूदा आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रभावी आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र का वैश्विक नेटवर्क आने वाली पीढ़ियों एवं धरती के स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

05

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, 2021 (LDAR) का मसौदा पेश किया, जिस पर लक्षद्वीप के लोगों द्वारा व्यापक रूप से रोष व्यक्त किया गया है।



2. लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का गठन

- यह विनियमन सरकार को, जिसे सामान्य तौर पर प्रशासक के रूप में पहचाना जाता है, को लक्षद्वीप में योजना और विकास प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार देता है, ताकि 'खराब लेआउट या अप्रचलित विकास' (bad layout or obsolete development) के रूप में पहचाने गए किसी भी क्षेत्र के विकास की योजना बनाई जा सके। हालांकि छावनी क्षेत्रों (cantonment areas) को इससे छूट दी गई है।
- इस प्रकार बनाया गया एक प्राधिकरण सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, एक नगर नियोजन अधिकारी और दो स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधियों के अलावा तीन 'विशेषज्ञ' सरकारी नामितों के साथ एक निगमित निकाय होगा।
- यह मसौदा विनियमन 'विकास' को परिभाषित करता है। विकास को भवन, इंजीनियरिंग, खनन, उत्खनन या अन्य कार्यों में संलग्न ऊपरी या निचली भूमि पर किसी पहाड़ी या उसके किसी भाग को काटने या किसी भवन या भूमि में किसी भी भौतिक परिवर्तन या किसी भवन या भूमि के उपयोग के रूप में परिभाषित करता है।

3. दंड का प्रावधान

- यह विनियमन प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। इसके अलावा, मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है जो किसी ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकती है जिसके दो से अधिक बच्चे हैं।

4. लक्षद्वीप के मसौदे पर विरोध क्यों?

- स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासक द्वारा क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। द्वीपसमूह की 60,000 से अधिक आबादी के साथ अच्छी तरह से न्याय नहीं गया है, जिनमें से 90% मुस्लिम हैं और लगभग 95% अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। एलडीए विनियमन को वापस लेने की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि कानून इस अधिकार के साथ ऐसी शक्तियां निहित करता है कि यह किसी भी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार कर सकता है और लोगों को उनकी इच्छा की परवाह किए बिना स्थानांतरित कर सकता है।
- यह जबरन बेदखली का प्रावधान करता है। मालिक को प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अपनी संपत्ति विकसित करने का दायित्व डालता है और साथ ही गैर-अनुपालन की स्थिति में उन्हें भारी दंड देने का भी प्रावधान करता है। द्वीप के समुदायों का एक घनिष्ठ समूह है जिसमें परिवार निकटता में रहते हैं। लोगों का मानना है कि यह विनियमन उनके द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही तौर-तरीकों को नष्ट कर देगा।
- लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन भी लाया गया है, जो स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ-साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रशासक की ओर से प्रस्तावित नए मसौदा कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है।
- कठोर विनियमन न तो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है और न ही सामाजिक रूप से व्यवहार्य है और इसका मसौदा तैयार करने से पहले लोगों के प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई थी।

5. लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति

- लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। यह सभी द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यह यहां का प्रमुख शहर भी है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत और एक आरामदायक जीवन शैली के साथ लक्षद्वीप की शोभा और आकर्षण को बढ़ाती है।
- लक्षद्वीप की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.82% है। प्रशासनिक आधार पर लक्षद्वीप को एक जिला माना जाता है।

06

WHO द्वारा जूनोटिक रोगों में होने वाली वृद्धि की जांच

1. चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एच5एन1 (H5N1), एवियन इन्फ्लूएंजा (avian influenza), मर्स (MERS), इबोला, जीका और संभवतः नोवेल कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) जैसे जूनोटिक रोगों के उद्भव और प्रसार का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल 'वन हेल्थ' (one Health) का गठन किया है।

2. उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल 'वन हेल्थ' के कार्य

- यह पैनल वैश्विक एजेंसियों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (the World Organisation for Animal Health - OIE) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को सलाह देगा कि भविष्य में विशेष रूप से जूनोटिक रोगों के प्रकोप को कैसे टाला जा सकता
- यह इसके लिए एक निगरानी ढांचा और वैश्विक कार्य योजना भी विकसित करेगा।
- विशेषज्ञ विभिन्न मानवीय गतिविधियों का भी बारीकी से अध्ययन करेंगे साथ ही प्राकृतिक वन्यजीव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों का आकलन करेंगे।
- इस पैनल के अनुसार खाद्य उत्पादन और वितरण एवं शहरीकरण जैसी गतिविधियों से जैव विविधता का नुकसान होता है साथ ही जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के साथ यह क्षति, विभिन्न जूनोटिक रोगों के तेजी से उभरने के पीछे एक संदिग्ध कारण है।



3. जूनोटिक रोग क्या हैं?

- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को जूनोटिक बीमारियाँ (Zoonotic diseases) कहा जाता है जो बैक्टीरिया, परजीवियों और वायरसों के कारण होती हैं। ऐसे रोग पहले जानवरों को संक्रमित करते हैं और फिर उनसे होते हुए ये बीमारियाँ इन्सानों को अपना निशाना बनाती हैं। हर चार में से तीन संक्रामक रोग जूनोसिस (Zoonosis) के कारण होते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को संदेह है कि COVID-19 भी एक जूनोसिस (Zoonosis) है।
- विश्व भर में पाँच लाख से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार महामारी कोविड-19 के स्रोत का सन्देह चमगादड़ों में होने पर जताया गया है। लेकिन कोविड-19 से पहले भी इबोला, MERS, West Nile बुखार सहित अन्य बीमारियाँ पशुओं से मनुष्यों में फैली और उनकी वजह भी मानव गतिविधियों से पर्यावरण पर बढ़ता दबाव माना गया था।
- हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत ऐसी पशुजनित बीमारियों से हो जाती है जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश मौतें निम्न और मध्य आय वाले देशों में होती हैं। इन्हीं रोगों के कारण पशुओं-मवेशियों को भी गम्भीर बीमारियाँ होती हैं और उनकी मौत हो जाती है जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है।

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन

- डब्ल्यूएचओ (संयुक्त राष्ट्र का निकाय) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गयी थी। यह सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और फिलहाल 150 देशों में लगभग 7,000 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं।

07

ग्रीनलैंड की नदियों में 'पारा' का उच्च स्तर

1. चर्चा में क्यों?

- हाल के एक शोध के अनुसार, ग्रीनलैंड की हिमचादरों (Greenland ice sheet) से जलापूर्ति होने वाले जल निकायों में पारे (प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली धातु) की उच्च सांद्रता पायी गयी है। वैज्ञानिकों ने देखा कि दक्षिण-पश्चिमी ग्रीनलैंड की नदियों में पारा सामग्री चीन की प्रदूषित अंतर्देशीय नदियों के समान थी।



2. प्रमुख बिन्दु

- शोधकर्ताओं ने बर्फ की चादर से जुड़ी नदियों और जल निकायों से पानी के नमूने एकत्र किए और सामान्य नदियों की तुलना में पारा की मात्रा का लगभग दस गुना पाया।
- नेचर जियोसाइंस (Nature Geoscience) में प्रकाशित पेपर में कहा गया है कि धातु की बड़ी मात्रा जैव संचय (bioaccumulation) के माध्यम से तटीय खाद्य जाल में प्रवेश कर सकती है और आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड एक प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातक क्षेत्र है।

3. पाये गए पारे का स्तर

- नदियों में विशेष रूप से घुले हुए पारे की मात्रा लगभग 1-10 एनजी एल-1 (किसी ओलंपिक स्विमिंग पूल में नमक-कण के आकार के बराबर पारे की मात्रा) पाई गई है।
- वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड हिमचादरों द्वारा पोषित जल निकायों में पारे का स्तर 150 एनजी एल-1 से अधिक पाया है।
- हिमनदों के चूर्ण (हिमनदों की नदियों को दूधिया दिखने वाला तलछट) द्वारा ले जाने वाले पार्टिकुलेट पारा 2000 एनजी एल-1 से अधिक की उच्च सांद्रता में पाए गए थे।

4. पारे के उच्च स्तर का कारण

- ग्रीनलैंड के नदियों या जल निकायों में पारे का उच्च स्तर किसी उद्योग अथवा अन्य मानवजनित गतिविधियों के कारण नहीं है। ग्लेशियरों के पहाड़ी ढलानों पर नीचे की ओर धीमी गति से विसर्पण करने के दौरान 'पारा-समृद्ध आधार-शैलों' (Mercury-rich bedrock) का अपक्षरण होता है और ग्लेशियर के पिघलने पर ये अपक्षरित शैल-कण प्रवाहित होकर जल-निकायों में पहुँच जाते हैं।
- शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि इससे वैश्विक स्तर पर पारा के प्रबंधन के तरीके में बदलाव लाएगा।

5. चिंताएँ

- अब तक पारे के प्रबंधन के सभी प्रयास इस विचार से आए हैं कि वातावरण में हम जो बढ़ती सांद्रता देख रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रत्यक्ष मानवजनित गतिविधि, जैसे उद्योगों से है। लेकिन ग्लेशियर जैसे जलवायु के प्रति संवेदनशील वातावरण से आने वाला पारा एक ऐसा स्रोत हो सकता है जिसे प्रबंधित करना कहीं अधिक कठिन हो सकता है।
- पारे की उच्च सांद्रता से जल प्रदूषण में वृद्धि होगी, क्योंकि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और हिमचादरें और ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं।
- पारा इन्सानों पर लंबे समय में असर करने वाला जहरीला धातु है। अन्य जीवों पर भी ये जहरीला है। इसलिए पर्यावरण में पारे की मौजूदगी एक गंभीर मुद्दा है। पर्यावरण में हरेक साल आने वाली पारे की आधी मात्रा ज्वालामुखी फटने से और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं से आती है।

6. शोध का महत्व

- इस प्रकार का निष्कर्ष ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को समझने में एक नया अध्याय खोलेगा।
- ग्लेशियर संभावित विषाक्त पदार्थों को भी ले जा सकते हैं, वे पानी की गुणवत्ता और तथा जल-धाराओं के समीप रहने वाले समुदायों को प्रभावित करेंगे, ऐसे में इससे गर्म होती दुनिया में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? इससे संबंधित आयामों का खुलासा हो सकता है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी की भू-रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को जानने में मदद मिलेगी।

7. पारे से संबंधित मिनामाटा संधि

- यह संधि 10 अक्टूबर 2013 को हुई। मिनामाटा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों पर इसके प्रावधान कानूनी रूप से लागू होते हैं।
- पर्यावरण पर पारे के प्रभावों को लेकर चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अभी तक 140 से अधिक देशों ने मिनामाटा संधि पर दस्तखत किए हैं। यह संधि पारे के प्रदूषण को रोकने की बात करती है।
- इस संधि का नाम मिनामाटा जापान के एक शहर के नाम पर पड़ा। टोक्यो से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित मिनामाटा में वर्ष 1950 के दशक में एक कंपनी से पारे के रिसाव के चलते लोगों को लाइलाज बीमारी हो गई। वर्ष 1956 में वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को 'मिनामाटा' नाम दिया। इसके बाद से ही दुनिया भर में पारे के इस्तेमाल को रोकने के लिए अभियान छिड़ा।

स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)



1. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थान शामिल

प्र. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये-

सूची-I (विश्व धरोहर स्थल)	सूची-II (संबन्धित राज्य)
(a) हायर बेनकल महापाषाण स्थल	1. वाराणसी
(b) भेड़ाघाट-लम्हेटाघाट	2. कर्नाटक
(c) कांचीपुरम के मंदिर	3. मध्य प्रदेश

(d) वाराणसी के घाट

4. तमिलनाडू

कूट:

	a	b	c	d
(A)	3	4	2	1
(B)	2	3	4	1
(C)	3	2	1	4
(D)	4	3	2	1

Ans: (B)

2. चक्रवात 'यास'

प्र. चक्रवाती तूफान, यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'यास' तूफान का नामकरण इस बार ओमान देश ने किया है।
2. 'यास' का मतलब होता है निराशा।
3. इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) 1, 2 और 3
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

3. चंद्र ग्रहण एवं सुपरमून

प्र. सुपरमून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सुपरमून पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का एक बड़ा आकार है।
2. सुपरमून का संबंध पूर्णिमा तिथि से है।
3. जिस दिन पूर्णिमा (Full Moon) तिथि हो और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर हो तो इस स्थिति में ही सुपरमून लगेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) 1, 2 और 3
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

4. चीन के 17+1 से लिथुआनिया का इस्तीफा

प्र. 17+चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 17+1 पहल चीन की अगुवाई वाला एक समूह है।
2. इसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में हुई थी।
3. इसका मकसद चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप (CEE) के सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।
4. साथ ही CEE क्षेत्र के विकास के लिए निवेश और व्यापार का इस्तेमाल होना था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 3 और 4
- (C) 1, 2 और 3
- (D) उपर्युक्त सभी

Ans: D

5. चीन का नया सामरिक राजमार्ग

प्र. चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रणनीतिक रूप से अहम राजमार्ग (highway) का निर्माण पूरा कर लिया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. चीन ने इस राजमार्ग का निर्माण यारलुंग जांगबो ग्रैंड कैनियन के बीच से होकर किया है।
2. यह चीन की सबसे गहरी खाई के रूप में जाना जाता है।
3. जिसकी अधिकतम गहराई 5009 मीटर है।

4. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जैंगबो कहते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 4
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 3 और 4
- (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (A)

6. भारत और ओमान के बीच दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण

प्र. भारत-ओमान सम्बन्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ओमान, भारत का समुद्री पड़ोसी है।
2. यह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के लिये एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है।
3. भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शनसीम अल बहश् सेना अभ्यास: अल नजाह एवं वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज आयोजित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) 1, 2 और 3
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

7. भारत-इजराइल के बीच कृषि में सहयोग के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर

प्र. भारत-इजराइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025 तक के लिए तीन साल के एक संयुक्त कार्यक्रम (IIAP) पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. नए कार्यक्रम के तहत कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र - 'विलेज ऑफ एक्सेलेंस' (Villages of Excellence) - तैयार किया जायेगा।

3. इसे 75 गांवों के भीतर 13 उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के साथ आठ राज्यों में बनाया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) उपर्युक्त सभी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (B)

8. व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति बनाम भारत सरकार

प्र. व्हाट्सएप की नई गोपनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. व्हाट्सएप के मुताबिक जो लोग प्राइवैसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वे व्हाट्सएप जुड़ी कई सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे।
2. व्हाट्सएप यूजर्स अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
3. यूजर्स वॉयस और वीडियो कॉल ना ही कर पाएंगे न उसका जवाब दे पाएंगे।
4. व्हाट्सएप आपके फोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा

और यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाय नहीं कर सकेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 3 और 4
- (C) 1, 2, 3 और 4
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

9. वैक्सीन पर्यटन

प्र. वैक्सीन पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वैक्सीन पर्यटन को “टीका प्राप्त करने के अतिरिक्त लाभ के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए विभिन्न देशों की यात्रा” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
2. वैक्सीन पर्यटन पैकेज में एक होटल में 20 दिन का आवास, भोजन, उड़ानें और कुछ दिनों के दर्शनीय स्थल शामिल हैं।

3. इस पैकेज की कुल लागत 1.3 लाख रुपये है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

10. हवाना सिंड्रोम

प्र. हवाना सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वर्ष 2020 में क्यूबा में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी, नाक से खून और बेचौनी हो रही है। इस मामले के बाद इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा था।
2. इस बीमारी के कुछ लक्षणों में मतली, थकान, मानसिक परेशानी और चक्कर आना शामिल हैं।

3. इस बीमारी से संक्रमित होने पर, रोगी को पीड़ादायक सनसनाहट और भिन्नभिन्न आवाज महसूस होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 2 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

11. क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज

प्र. क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वर्ष 1857 में इस रोग की पहचान सबसे पहले तमिलनाडू के क्यासानूर जंगल (Kysanur Forest) के एक बीमार बंदर में की गई थी, तब से प्रतिवर्ष 400-500 लोगों के इस रोग से ग्रसित होने के मामले सामने आए हैं।
2. यह रोग कीट-जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार (tick-borne viral haemorrhagic fever) है जो भारत के दक्षिण-पश्चिमी भाग के लिए स्थानिक है।
3. यह फ्लैविविरिडे (Flaviviridae) परिवार के एक मछर के कारण होता है।

4. KFD वायरस के भंडार के रूप में कार्य करते हुए, संक्रमित हार्ड टिक (infected hard ticks) के काटने से मनुष्यों में वायरस फैलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 2 और 4
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (A)

12. ‘नेट जीरो बाय 2050’ (Net Zero by 2050)

प्र. 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन (NZE) हेतु ‘नेट जीरो बाय 2050’ नाम से अपना रोडमैप जारी किया गया है।
2. यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोडमैप है जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप-26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

13. जीआई प्रमाणित 'शाही लीची'

प्र. जीआई प्रमाणित शाही लीची (GI certified Shahi Litchi) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची (Shahi Litchi) बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था।
2. शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण, मुजफ्फरपुर स्थित 'लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार' को दिया गया है।
3. बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले

और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है।

4. उल्लेखनीय है कि चीन के बाद भारत विश्व में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

14. व्हाइट फंगस

प्र. व्हाइट फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह हमारे आसपास व त्वचा पर ही मौजूद रहता है।
2. इसका असली नाम, कैंडिडियासिस है।
3. यह आईसीयू में अक्सर पाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

15. सूखा राशन दें, प्रवासी कामगारों के लिए सामुदायिक रसोई चलाएं: SC

प्र. सूखा राशन और सामुदायिक रसोई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. आत्मनिर्भर भारत योजना' वर्ष 2020 के मई और जून में प्रवासी श्रमिकों को शुष्क राशन देने के लिए शुरू की गई थी।
2. प्रवासी मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त उपाय करने के लिए भारत संघ रेल मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

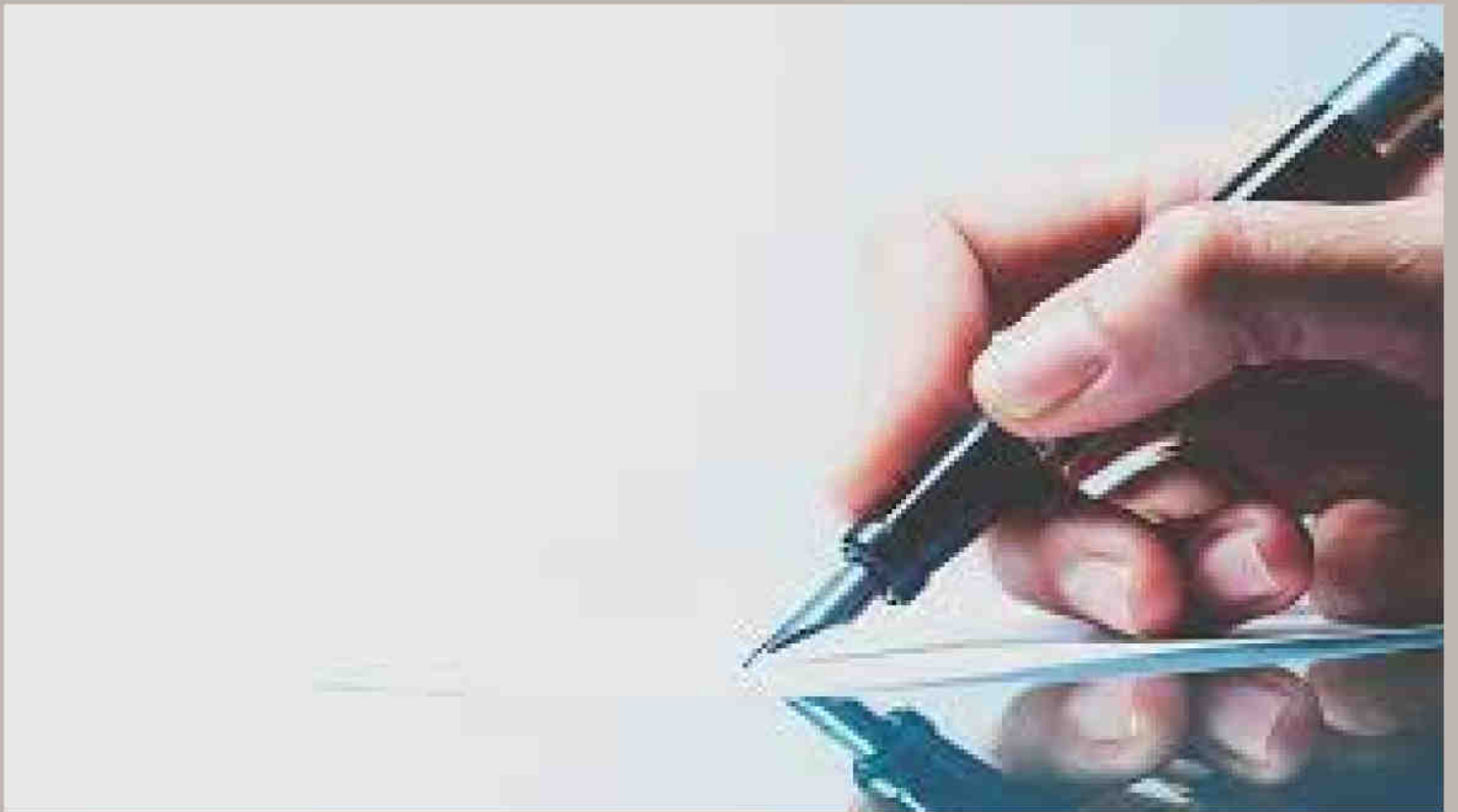
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)



स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)





01



03



05

01

पूर्ण चंद्रग्रहण (Total lunar eclipse), ब्लड मून (blood moon) और सुपरमून (Supermoon) की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये।

02

चीन का 17+1 सहयोग मंच क्या है, जिसे लिथुआनिया ने इसे 'विभाजनकारी' (divisive) बताया है? परीक्षण कीजिये।

03

हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रणनीतिक रूप से अहम राजमार्ग (highway) का निर्माण पूरा कर लिया है। यह भात के हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? मूल्यांकन कीजिये।

04

हाल ही में भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है यह किस प्रकार समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा? टिप्पणी कीजिये।

05

हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 तक के लिए तीन साल के एक संयुक्त कार्यक्रम (Indo-Israel Agriculture Action Plan – IIAP) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते किस प्रकार कृषि क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेंगे?

06

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बार फिर फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है। इससे लोगों की निजी गोपनीयता कितनी प्रभावित होगी? समीक्षा कीजिये।

07

दुनिया भर में "वैक्सीन टूरिज्म" शब्द गति पकड़ रहा है। वर्तमान समय में यह कितना प्रासंगिक है? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

08

हवाना सिंड्रोम क्या है? क्या ये एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार हैं?

09

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा जारी शुद्ध शून्य उत्सर्जन (NZE) हेतु 'नेट जीरो बाय 2050' रोडमैप क्या है?

10

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण देश में सभी राज्यों को फंसे हुए प्रवासी कामगारों को बिना किसी राशन-कार्ड के शुष्क राशन वितरित करने और उनके लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम नैतिक रूप से कितना सही है मूल्यांकन कीजिये।

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparalleled track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individual's capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies. The distance learning material is comprehensive, concise and exam-oriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

 YouTube **dhyeyaias**

dhyeyaias.com

 /dhyeya1

STUDENT PORTAL

Dhyeya IAS Now on Telegram

We're Now on Telegram



Join Dhyeya IAS Telegram

Channel from the link given below

"https://t.me/dhyeya_ias_study_material"

You can also join Telegram Channel through
Search on Telegram

"Dhyeya IAS Study Material"

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारे ईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें** अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से **Subscribe** करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending "Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

Step by Step guidance for Subscription:

- **1st Step:** Fill Your Email address in form below. you will get a confirmation email within 2 min.
- **2nd Step:** Verify your email by clicking on the link in the email. (Check Inbox and Spam folders)
- **3rd Step:** Done! you will receive alerts & Daily Free Study Material regularly on your email.

Subscribe



ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: **9205962002**
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaiaas.com